खंड: 6, अंक: 05 मई 2023 DELHIN/2021/84711

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

कर्नाटक 2023: परिवर्तनीय लोकतांत्रिक परिदृश्य

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रो सुनील कुमार चौधरी

संपादकीय मण्डल

डॉ रमेश भारद्वाज
डॉ संध्या वर्मा
डॉ महेश कौशिक

डॉ अभिषेक नाथ
डॉ आशीष कुमार शुक्ल
राम किशोर

© सीजीएस 2022

रूपांकन: काजल व सृष्टि

संश्लेषण

कर्नाटक 2023: परिवर्तनीय लोकतांत्रिक परिदृश्य

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्यः कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम का निहितार्थ
   — रमेश चौधरी 1—6
2. कर्नाटक चुनाव 2023: परिवर्तनीय लोकतांत्रिक परिदृश्य
   — कुन्दन राज, पुजा भारती 7—10
3. कर्नाटक राज्य चुनाव 2023: परिवर्तनीय कारक — पप्पला गीतिका सौम्या 11—14
4. कर्नाटक की चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार का परिवर्तनीय परिदृश्य
   — विकास यादव 15—17
5. कर्नाटक में युवाओं के मतदान व्यवहार का एक अध्ययन
   — हदुंगरा नरजरें 18—21
6. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्वः कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में एक अध्ययन — चंद्रिका आर्य 22—26
7. कर्नाटक की चुनावी राजनीति में परिवर्तित प्राथमिकताओं के मध्य जनता दल (सेक्युलर) की परिस्थिति — डॉ काजल 27—30
8. कर्नाटक विधानसभा चुनावः 2018 व 2023 का एक तुलनात्मक अध्ययन
   — सृष्टि 31—35
9. कर्नाटक विधानसभा चुनावः एक विश्लेषण — सुमेर राम 36—40
10. उत्तरी कर्नाटक में मतदान व्यवहार की परिवर्तित प्रकृतिः बेलगावी क्षेत्र का एक अध्ययन
    — दृष्टि साह 41—44

सम्पादकीय

समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रकाशन की निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता सहित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रित कर उन्हे प्रकाशित करना होता है। व्यवसायिकता और व्यवहारिकता के मानदंडों में इन लेखों को विश्लेषित करना तथा नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में इनको उचित प्रयोग में लाना प्रकाशिय सरोकारों को और अधिक चुनौतिपूर्ण बना देता है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 58वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 2023 को भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक चुनावी वर्ष के रुप में संबोधित किया जा सकता है। लोक सभा 2024 से पूर्व विभिन्न राज्य विधान सभाओं में होने वाले त्रैमासिक चुनाव एक सशक्त एवं सुदृढ़ लोकतंत्र की दृष्टि से अनेक आयाम प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल, गुजरात एवं पूर्वोतर राज्यों के पश्चात दक्षिण भारत में मई 2023 का कर्नाटक विधान सभा चुनाव विविध दष्टिकोणों से एक परिवर्तनीय परिदृश्य को इंगित करता है।

पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के छः राज्यों से संलग्न, पाँच करोड़ से अधिक जनसंख्या वासित, चतुर्थ–स्तरीय प्रशासनिक तथा बहुजातियता एवं बहुधार्मिकता में विभक्त कर्नाटक चुनावी लोकतंत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूण प्रदेश है। 30 जिलों तथा 224 विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित कर्नाटक राज्य को *दक्षिण के द्वार* के रुप में भी वर्णित किया जाता है। मई 2023 का कर्नाटक विधान सभा चुनाव कांग्रेस, भाजपा एवं जनता दल (सेक्यूलर) के मध्य त्रिकोणिय संघर्ष को रेखांकित करता है। पक्ष प्रदर्शन, आरोपण एवं दोषारोपण के परिदृश्य में तीनो राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अदम्य सार्मथ्य और साहस का परिचय देते हुए मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयत्न किया। *मठ, मस्जिद एवं मिशनरी* के रुप में *एम3 विमर्श* ने संपूर्ण राज्योय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया। रैलियों व अभियानों के विस्तृत व वृहत प्रचार–प्रसार सहित प्रमुख दलों के बागी नेताओं तथा विवादास्पद टिप्पणियों ने भी कर्नाटक विधान सभा 2023 के चुनाव को मुख्य राष्ट्रीय परिदृश्य में रखा।

राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'कर्नाटक 2023: परिवर्तनीय लोकतांत्रिक परिदृश्य' विषय पर लेख आमंत्रित किये। दस उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल

बुधवार, 14 जून 2023

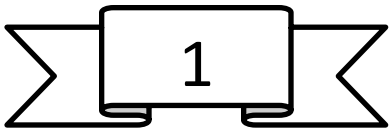

समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्यः कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम का निहितार्थ

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

कर्नाटक राज्य विधानसभा के सभी 224 सदस्यों के निर्वाचन के लिए हाल ही में 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। राज्य के सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी परिणाम की घोषणा 13 मई 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा की गई। इस विधानसभा चुनाव में 73-19% मतदान हुआ, जो कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनावों के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 135 सीटों के साथ भारी बहुमत से चुनाव जीता, कांग्रेस का यह प्रदर्शन राज्य विधानसभा चुनावों लगभग पिछले तीन दशकों का कर्नाटक में सीटों और मत प्रतिशत के आधार में सबसे बड़ी चुनावी विजय है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल {सेक्युलर} {JDS} को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ये राजनीतिक दल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

वर्तमान भारतीय राजनीतिक और चुनावी परिदृश्य में कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए यह जनादेश अप्रत्याशित हैं, कांग्रस का 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत और कर्नाटक के सभी क्षेत्रों और जातीय, धार्मिक समूहों से समर्थन प्राप्त करना कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित था। इस विधानसभा चुनाव में जनता दल (सेकुलर) के समर्थन में कमी से यह भी स्पष्ट हो गया, राज्य की लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में तीसरे खिलाड़ी या विकल्प के लिए स्थान और संभावना अत्यंत गौण हो गई है। इन चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में आधी से भी कम सीटें जीतीं, लेकिन इन चुनावी परिणामों का एच.डी. देवगौड़ा और एच.डी. कुमारस्वामो द्वारा नेतृत्व जनता दल (सेक्युलर) को राजनीतिक रुप से अपरिवर्तनीय गिरावट का सामना करना पड़ा।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव का राजनीतिक परिदृश्य में निहितार्थ

भारत की सबसे पुरानी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस बीच, इस चुनाव में, भाजपा को पिछले राज्य विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में संख्या के लिहाज में महत्वपूर्ण नुकसान के साथ सिर्फ 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जनता दल (सेकुलर) का प्रदर्शन भी इस बार काफी निराशाजनक रहा जेडीएस को इस बार मात्र 19 सीट प्राप्त हुई जो कि पिछले चुनाव की तुलना में लगभग आधी हैं, वास्तविक रूप से मूल्याकंन किया जाए तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार होने से जेडीएस का राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मुख्य निहितार्थ इस प्रकार हैं–

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत और कांग्रेस का पुनः आत्मविश्वास प्राप्त करना

पिछले साल लगभग इसी समय कांग्रेस सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी। विपक्षी दलों के संदर्भ में, जो गैर भाजपा या भाजपा समर्थित दल फिलहाल राज्यों में सतारूढ़ है तो कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से कांटे की टक्कर थी जो फिलहाल दो राज्यों (पंजाब और दिल्ली) में सत्तारूढ़ है। लेकिन पिछले साल हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से विजय और कर्नाटक में इस प्रभावशाली जीत के साथ, कांग्रेस वर्तमान समय में चार भारतीय राज्यों में सत्तारूढ़ है। यह संख्या संकेत देती है कि हाल के वर्षों में अपनी चुनावी प्रासंगिकता खोने के बावजूद, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसी पार्टी बनी हुई है जो भाजपा का मुकाबला और चुनौती दे सकती है।

चाहे राज्य स्तर के चुनाव हों या राष्ट्रीय स्तर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के विजयी रथ ने पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस को कुचल दिया है। लेकिन 2023 कांग्रेस पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, कर्नाटक चुनावों के नतीजे कांग्रेस को बहुत जरूरी आत्मविश्वास देंगे जब वह सीधे चुनावी मुकाबले में बीजेपी का सामना करेंगे, जैसे कि इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा चुनावों में। 2018 में कांग्रेस ने तीनों राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार गिर गई। कर्नाटक में बड़ी सफलता के बाद, पुनर्जीवित कांग्रेस 2018 की पुनरावृत्ति का प्रयास करने और 2023 में इन तीन चुनावी राज्यों में जीत हासिल करने की उम्मीद अवश्य करेगी।

विपक्षी एकता व एकजुटता के संदर्भ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का निहितार्थ

कांग्रेस की यह जीत ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, फारूख अब्दुल्ला, एमके स्टालिन और शरद पवार जैसे विपक्षी

नेता 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने की पहल कर रहे हैं। कांग्रेस अब खुद को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में फिर से स्थापित कर रही है, यह देखना दिलचस्प होगा कि ये विपक्षी नेता और दल इस विपक्षी एकता में कांग्रेस के नेतृत्व को कैसे स्वीकार करते हैं।

इस चुनाव के नतीजे अन्य विपक्षी दलों की तुलना में कांग्रेस की स्थिति को ष्आइमस इंटर पैरेसष (समान में प्रथम) के रूप में भी मजबूत करेंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ संयुक्त मोर्चा के निर्माण का निर्णय करते हैं तो कांग्रेस के पास अब अधिक सौदेबाजी की संभावना होगी। यदि 2024 से पहले संयुक्त मोर्चा आकार लेता है, तो कांग्रेस अब अपनी हालिया चुनावी जीत के बाद अधिक सीट और नेतृत्व की मांग करने की स्थिति में होगी। जो कि विपक्षी एकता और एकजुटता के लिए अवश्य विवादास्पद साबित हो सकती है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में निहितार्थ

भाजपा ने 2014 के बाद से राज्य और राष्ट्रीय दोनों चुनावों में अक्सर और सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा और निर्भर किया है। हालांकि मोदी मैजिक न राज्य विधानसभा चुनावों में कई मौकों पर बीजेपी के लिए अभूतपूर्व योगदान किया है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव नतीजे साबित करते हैं कि मजबूत और विश्वसनीय स्थानीय नेतृत्व और चेहरे की अनुपस्थिति में यह हमेशा पर्याप्त नहीं है।

प्रफुल्ल केतकर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति का जायजा लेने का सही समय है। क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत और प्रभावी नेतृत्व के बिना, प्रधान मंत्री मोदी का करिश्मा, विकास और हिंदुत्व एक वैचारिक गोंद के रूप में पर्याप्त नहीं होगा। जब राज्य–स्तरीय शासन प्रभावी होता है, तो सकारात्मक कारक, हिंदुत्व विचारधारा, विकास और पीएम मोदी का नेतृत्व भाजपा के लिए वास्तविक संपत्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को किसी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा। यह कर्नाटक में भाजपा के राज्य स्तरीय नेतृत्व से जुड़ी समस्याओं और कमजोरियों को इंगित करता है।

हालांकि इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी के लिए आक्रामक प्रचार किया, लेकिन वह पूरे चुनाव के दौरान राजनीतिक किनारे पर रहे। इसके अलावा, सीएम बसवराज बोम्मई सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत

चेहरा साबित नहीं हुए। तो इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ यही उभर कर आता है कि स्थानीय नेतृत्व और सरकारों को मजबूती से कार्य करना होगा उदाहरणस्वरूप भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के उपयोगी बने रहने के बावजूद बीजेपी को सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में मजबूत और प्रभावी चेहरा होने का फायदा मिला है।

जनता दल (सेक्युलर) के संदर्भ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का निहितार्थ

2018 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। यहां तक कि एचडी कुमारस्वामी के शीर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसे मुख्यमंत्री का पद भी हासिल किया था। 2023 के चुनावों में जनता दल (एस) केवल 19 सीटें जितने में सफल रही, इन परिणामों के बाद वे न तो किंग और न ही किंगमेकर बनने की स्थिति में है, जनता दल (सेक्युलर) अब अपने वोट और सीट शेयरों में भारी कमी देखने के बाद अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

कर्नाटक विधानसभा नतीजों के बाद, जनता दल (सेक्युलर) को अपने भविष्य के बारे में तीखे सवाल का सामना करना पड़ेगा और क्या यह वास्तव में भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दिग्गजों के लिए एक मजबूत स्थानीय जवाब के रूप में उभर सकता है। इसके अलावा, यह अब उन क्षेत्रीय दलों की बढ़ती सूची का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के टकराव के मध्य अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।

अन्य विपक्षी दलों के संदर्भ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम

कर्नाटक में चुनाव मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता विरोधी लहर जसे स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया। जबकि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय अपील व राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के व्यापक विषयों पर भरोसा किया। परंतु भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दे राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस के मुख्य आरोप रहे जो मतदाताओं को प्रभावित किए।

कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार में राज्य सरकार को ष्भ्रष्टष के रूप में पेश किया और अपनी पांच गारंटियों, कल्याणकारी उपायों और समाज के विभिन्न वर्गों पर लक्षित रियायतों के साथ मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को लुभाया। इस चुनाव के नतीजे अन्य विपक्षी दलों के लिए एक अनुस्मारक होंगे कि जब राज्य स्तर के चुनावों की बात आती है तो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना मतदाताओं के मध्य अच्छा और बेहतर प्रभाव डाल सकता है।

भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण भारत में उसका राजनीतिक अस्तित्व

भाजपा पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण भारत में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसलिए, कर्नाटक में चुनावी हार पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगी, क्योंकि यह एकमात्र बड़ा दक्षिणी राज्य था जहां वह सत्ता में थी, कर्नाटक भाजपा के लिए चुनावी राजनीति के परिपेक्ष्य में दक्षिण के द्वार के नाम से जाना जाता रहा हैं। पुडुचेरी को छोड़कर, जहां भाजपा एआईएनआरसी के साथ गठबंधन में है, भाजपा की अब दक्षिण भारत में कोई उपस्थिति नहीं है। भाजपा को अब इस क्षेत्र में अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा, खासकर तेलंगाना में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले, जहां वह सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से मुकाबला करने की उम्मीद कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए भाजपा को आंध्र प्रदेश में एक उपयुक्त गठबंधन निर्माण करने की आवश्यकता है जहां भाजपा के पास तेलगु देशम पार्टी और वाईआरएस कांग्रेस पार्टी दोनों ही संभावित विकल्प है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसांगिक है, इन चुनावों में भाजपा की हार इनकी स्थानीय नेतृत्व की कमी और स्थानीय शासन व प्रशासन की कमजोरियों को इंगित किया है जिसके लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जल्द ही उपयुक्त कदम लेना जरूरी है। इस चुनाव के नतीजों ने कर्नाटक राज्य के तीसरे अन्य विकल्प के रूप जनता दल (सेकुलर) के राजनीतिक अस्तित्व और उसके नेता एचडी कुमारस्वामी की महत्वाकांक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर विजयी रही, परंतु ये कांग्रेस की इस जीत का श्रेय कर्नाटक कांग्रेस कुशल के स्थानीय नेतृत्व और नेताओं की एकजुटता को दिया जाना चाहिए।

संदर्भ–सूची

Hindustan Times, *Karnataka election results: Congress wins by biggest vote share in 34 years.* 14 May 2023

The Hindu, *Assembly elections: Turnout at 73.19% is a historic high for Karnataka.* 11 May 2023

Ketkar, prafulla, *Karnataka results: opportune time for introspection.* Organiser

♦♦♦♦♦

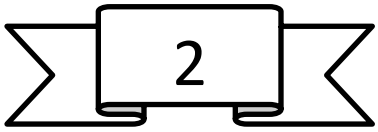

कर्नाटक चुनाव 2023: परिवर्तनीय लोकतांत्रिक परिदृश्य

कुन्दन राज

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पुजा भारती

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कर्नाटक देश के राजनीतिक परिदृश्य में अत्यधिक महत्व रखता है। राजनीति के महत्व से इसे प्रायः दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो इसे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य बनाता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछले नौ वर्षों से केंद्रीय स्तर पर सत्ता में है, किन्तु उसे दक्षिण भारत में सुदृढ़ पकड़ बनाने के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ा है।

पिछले विधानसभा कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने में सक्षम रही, जिससे अन्य दक्षिणी राज्यों में भी सफलता की एक उम्मीद जगी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को दक्षिणी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में देखा। तथापि, इन आकांक्षाओं को हाल के विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जिससे भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा है। दक्षिणी राज्यों में आगे बढ़ने की भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कांग्रेस ने निर्णायक विजय प्राप्त की। इस परिणाम ने दक्षिण भारत में भाजपा की कहानी और रणनीति को कड़ी चुनौती दी है।

कर्नाटक का राजनीतिक परिदृश्य भारतीय राजनीति की गतिशीलता को आकार देने तक की क्षमता रखता है। राज्य का महत्व दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी भूमिका से उत्पन्न होता है जो इसे राजनीतिक दलों के लिए एक प्रमुख युद्धक्षेत्र बनाता है। विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत देश के समग्र राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।

कर्नाटक में सरकार की संसदीय प्रणाली है जिसमें दो सदन हैं– विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा में 224 सदस्य होते हैं जो पांच साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि परिषद 75 सदस्यों का एक स्थायी निकाय है जिसमें एक तिहाई हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। हाल ही में 10 मई 2023 को हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख पार्टियां रही जिसका नेतृत्व क्रमशः बसवराज बोम्मई सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी ने किया। 13 मई 2023 को घोषित परिणाम आश्चर्यजनक थे, क्योंकि कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) को क्रमशः 66 और 19 सीटें प्राप्त हुईं। पिछले 2018 के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी 78 सीटें प्राप्त किए थे और जनता दल (सेक्युलर) के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। यद्यपि, 2019 में गठबंधन टूट गया जिसके कारण भाजपा ने बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई जो जुलाई 2021 के पश्चात् बसवराज बोम्मई जी के द्वारा द्वारा सफल बनाई गई।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछली बार गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक उथल–पुथल चरम पर थी। और 2023 का चुनाव से एक ऐसा अपेक्षा किया जा रहा था की यह कर्नाटक में राजनीतिक स्थिरता बनाएगा। वैसे चुनाव से पहले कर्नाटक में कई राजनीतिक खेल और विवाद देखने को मिले जैसे– कांग्रेस पार्टी का अपने घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा एक बड़ा विवाद बनकर खड़ा हुआ। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दा को भगवान हनुमान के अपमान से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूरे कर्नाटक में सार्वजनिक रैलियों में मतदाताओं में जोश भरने के लिए श्बजरंग बली की जयश के नारे लगाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की, आरोप लगाया कि कांग्रेस का लक्ष्य भगवान हनुमान के भक्तों को बंद करने का था और भगवान राम के संबंध में उनके पिछले कार्यों का जिक्र किया। बजरंग दल से जुड़े विवाद के अतिरिक्त कर्नाटक चुनाव में मुफ्त सुविधाओं की राजनीति और आरक्षण से जुड़े कारक भी चुनाव पर अधिक प्रभावशाली रहे। इन कारकों ने मतदाता प्राथमिकताओं और पार्टी रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चुनाव से पहले, दलबदल की राजनीति बड़े स्तर पर थी क्योंकि विभिन्न दलों के राजनेताओं ने अपने दल में परिवर्तन लिया था। 19 फरवरी 2023 को भाजपा नेता एच.डी. थम्मैया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। 9 मार्च 2023 को बीजेपी एमएलसी पुत्तन्ना भी कांग्रेस में

सम्मिलित हो गए। एक अन्य प्रमुख नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने 16 अप्रैल, 2023 को भाजपा छोड़ दी और अगले दिन कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। लक्ष्मण समेत कई अन्य नेता सावदी एस अंगारा, एम पी कुमारस्वामी और आर. शंकर ने चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी।

इन दलबदल की राजनीति में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने और चुनाव की गतिशीलता को आकार देने की क्षमता थी। इन्होंने पार्टी संरेखण, रणनीतियों और चुनावी गणनाओं में परिवर्तन लाए राजनीति की तरल प्रकृति और चुनावी परिणामों में व्यक्तिगत राजनीतिक गठबंधनों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुफ्त सुविधाओं की राजनीति आरक्षण और दलबदल की राजनीति ने कर्नाटक चुनाव में और जटिलताएँ बढ़ा दीं जिससे राजनीतिक अभियान अवधि के दौरान मतदाताओं की धारणाएँ और पार्टी की गतिशीलता प्रभावित हुई। देश भर में चुनावों में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कर्नाटक कोई अपवाद नहीं है। राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए अपने अभियानों में जाति–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है।

कर्नाटक में जाति–आधारित राजनीति का इतिहास रहा है, जिसमें लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के मध्य प्रमुख झगड़ा रहा है। ये दोनों जातियां पारंपरिक रूप से सत्ता पर काबिज रही हैं और राज्य में प्रमुख समुदाय होने का दावा करती हैं। सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, कर्नाटक में एमपी और एमएलए सीटों में से लगभग 50% सीटों पर इनका ही अधिग्रहण रहा है।

तथापि, जाति–आधारित राजनीति के मध्य जनसंख्या का कुछ वर्ग, विशेष रूप से शिक्षित वर्ग, जो एक स्थिर एकल–दलीय सरकार चाहते थे। यह भावना कर्नाटक के हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम से प्रभावित थी। कई बुद्धिजीवियों ने भविष्यवाणी की थी कि जनता दल (सेक्युलर) (जेडीएस) एक बार फिर महत्वपूर्ण (किंगमेकर) भूमिका निभाएगी, जैसा कि उसने 2018 विधान सभा चुनाव में किया था। यद्यपि, जनता दल (सेक्युलर) को नवीनतम चुनाव 2023 में बड़ा झटका लगा यह पहले जीती गई 37 सीटों की तुलना में केवल 19 सीटें प्राप्त करने में सफल रही।

जनता दल (सेक्युलर) के प्रदर्शन में यह परिवर्तन मतदाता प्राथमिकताओं की उभरती गतिशीलता और अधिक स्थिर राजनीतिक वातावरण की इच्छा को दर्शाता है। जबकि जातिगत विचार प्रभावशाली बने हुए हैं, जनसंख्या का एक वर्ग ऐसा भी है जो जाति–आधारित राजनीतिक गठबंधनों के स्थान पर शासन और एक सुदृढ़ एकल–दलीय सरकार को महत्व देता है।

कर्नाटक में 2023 विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जीती गई सीटों की संख्या के मामले में एक बड़ा झटका लगा, पार्टी अपनी पिछली 104 सीटों की तुलना में केवल 66

सीटें प्राप्त करने में सफल रही। यद्यपि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि भाजपा को प्राप्त वोटों का प्रतिशत अपेक्षाकृत स्थिर रहा। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले, जबकि पिछले चुनाव में उसे 36-35% वोट मिले थे।

तथापि, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए अपेक्षित सीटों की संख्या प्राप्त नहीं कर पाई, पर सबसे बड़ा झटका भाजपा के लिए यह है कि भाजपा की दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनाव जीतने के प्रयासों की गति धीमी हो गई। भाजपा दक्षिणी क्षेत्र मं अपनी उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास कर रही थी और कर्नाटक ने उस रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यह पराजय दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय पार्टियों की प्रमुखता तोड़ने और दक्षिण भारतीय राज्यों में सुदृढ़ता स्थापित करने में कठिनाइयां हैं। पार्टी के मतदान अंश में तो स्थिरता रही है, किन्तु यह दिखाता है कि इस समर्थन को सीटों में परिवर्तित करने और क्षेत्र में सत्ता सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी कदम और समायोजन की आवश्यकता है। फिर भी कर्नाटक चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन से उन्हें अधिक सीखने का अवसर मिलेगा और यह दक्षिणी राजनीतिक मंच में भविष्य की रणनीतियों को आकार देगा।

कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण विजय के पश्चात् भी, चुनौतियाँ बनी रही, विशेषकर मंत्रालयों के आवंटन को लेकर। मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के मध्य तनाव सामने आया। अंततः सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, और डीके शिवकुमार को उनके डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया। अब जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है कि वह शासन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और राज्य को प्रभावी ढंग से चलाए। कर्नाटक में उनके राजनीतिक प्रयासों की सफलता केवल तभी निर्धारित की जा सकती है, जब आने वाले दिनों में सरकार का प्रबंधन और संचालन कैसे होता हैं।

♦♦♦♦♦

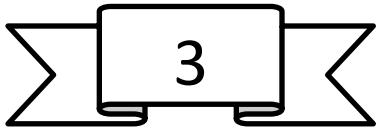

कर्नाटक राज्य चुनाव 2023: परिवर्तनीय कारक

पप्पला गीतिका सौम्या

विद्यार्थी, गार्गी कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

कर्नाटक राज्य में मुख्य राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस थे, तथापि अन्य में सीपीआई, सीपीआई (एम) और एमईएस भी सम्मिलित हैं। कर्नाटक में राजनीति की परिवर्तनीय प्रकृति का इन राजनीतिक दलों के मध्य निरंतर प्रतिस्पर्धा के कारण प्रमुख प्रभाव पड़ा है। कर्नाटक में प्रतिस्पर्धा किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं अपितु राजनेताओं के मध्य है। भाजपा ने पहली बार कर्नाटक में 2008 में बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और बाद में कांग्रेस–जेडीएस गठबंधन के पतन के पश्चात् 2019 में सरकार बनाई। भाजपा का विकास और आर्थिक विकास के संबंध में मजबूत लक्ष्य है जबकि कांग्रेस का लक्ष्य कल्याण उन्मुख राजनीति, निर्धनता उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समावेशिता के संबंध में सामाजिक न्याय पर आधारित था।

जबकि 2019 के चुनावों की 2023 के चुनावों से तुलना करने पर हम निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जिन्होंने पार्टी प्रणाली को परिवर्तित कर दिया, वे निम्न प्रकार से है।

प्रथमतः वर्ग प्रभाव के कारण राज्य की जनता महँगाई, बेरोजगारी आदि में निरन्तर वृद्धि से दुःखी थी। हालाँकि कर्नाटक के पश्चिम और दक्षिण में शहरीकृत क्षेत्रों में भाजपा को कुछ सीटें प्राप्त हुईय कर्नाटक के उत्तर की ओर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेष रूप से कल्याणकारी योजनाओं पर खराब प्रभाव, भ्रष्टाचार, उन क्षेत्रों में कम विकास, शिक्षा संस्थानों की खराब उपलब्धता, सरकारी प्रदर्शन और नीतियां के खराब कार्यान्वयन के कारण निराश थे, जिसके कारण भाजपा उनका विश्वास प्राप्त करने में विफल रही। और साथ ही कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम समुदाय ने अधिकतर उनकी अन्न भाग्य योजना के कारण कांग्रेस का समर्थन किया।

अन्य कारण भाजपा द्वारा उम्मीदवार के चयन में हो सकते हैं, भाजपा द्वारा अपने लोकप्रिय उम्मीदवार पेश करने में विफल रहने के कारण कुछ लोग असंतुष्ट थे। और कुछ नेताओं ने यह भी शिकायत की कि कैसे पार्टी में निर्णय केवल कुछ ही लोग लेते थे और प्रमुख नेता कांग्रेस में

सम्मिलित होने के लिए पार्टी छोड़ देते थे और कांग्रेस ने इस अवसर का फायदा उठाया क्योंकि लोगों का झुकाव पार्टी की तुलना में व्यक्तियों की ओर अर्थात उम्मीदवार की ओर अधिक था।

वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कई राजनीतिक खेल खेले जा रहे थे, अधिकतर चुनाव अभियानों में होता है, किन्तु कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों के कुछ भागों में, उदाहरण के लिए, गंगावती चुनाव क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जनता अपने उम्मीदवार को आर्थिक रूप से सहायता करके चुनाव जिताने के लिए उत्सुक थे।

लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी क वर्तमान विधायक जी जनार्दन रेड्डी के काम पर अपनी संतुष्टि दिखाई, कि वह लोगों की चिंताओं को कैसे सुनते हैं और उन्होंने विकास में और महामारी के समय में कैसे सहायता की, उन्होंने आगे कहा कि वह उस क्षेत्र में शासन करने वाले लोगों के साथ काम करते हैं और गंगावती से संबंधित लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने का अनुरोध किया, और उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव प्रचार में उन्हें जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, वे उन्हें प्रदान करेंगे।

यही कारण है कि शासन में परिवर्तन देखने के लिए हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। जब राजनीतिक मामलों या यहां तक कि वोट देने की बात आती है तो अधिकांश लोगों की रुचि कम होती है, किन्तु यदि नेता जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग आदि की भूमिका के बावजूद लोगों की इच्छा से चुना जाता है तो हम लोकतंत्र के सार का पालन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से, लोगों को यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि उनका नेता उनके लिए परिवर्तन और विकास लाएगा।

इसके साथ–साथ कुछ अन्य कारण भी थे, जैसा कि हम देख सकते थे कि लिंगायत समुदाय के वोटों ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटों को सुरक्षित करने में सक्षम थी, जबकि भाजपा ने सुधार करने का वादा करके लिंगायत, वोक्कालिंगा, ओबीसी, आदिवासियों से बहुमत वोट प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। परंतु यह एक कारण था कि वोट बैंक में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इस बार बीजेपी लिंगायत समुदाय का विश्वास प्राप्त करने में विफल रही (पार्टी में उम्मीदवारों के परिवर्तन के कारण) हालांकि उसने सुधार करने का प्रयास किया, किन्तु कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

तथापि भाजपा द्वारा कुछ चुनाव–क्षेत्रों में विकास में वृद्धि भी देखो जा सकती है, जैसे कि बीदर–कलबुर्गी रेलवे लाइन का पूरा होना, बीदर–कलबुर्गी–बेल्लारी राजमार्ग का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी, लोगों का मानना है कि विकास में अधिक लंबा समय लगा और उनका कहना था कि उनके क्षेत्र विशेष में ये परिवर्तन हुए हैं। या विकास केवल तभी किया

गया जब चुनाव का माह नजदीक था और लोगों ने अंततः यह विश्वास खो दिया कि 2019 में शासन करने वाले भाजपा नेता 2023 का चुनाव जीतने पर भी यही दोहराएंगे।

यद्यपि भाजपा ने आधारिक संरचना में विकास किया किन्तु उम्मीदवारों के चयन के कारण पार्टी में आंतरिक गड़बड़ी के कारण, पार्टी अधिकतर प्रधानमंत्री (केंद्रीय पार्टी पर निर्भर) पर निर्भर रही, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों और उनके मुद्दों से जुड़ना था और राहुल गांधी ने बने रहने का प्रयास किया।

एक अन्य कारण सांप्रदायिक मुद्दा भो था, क्योंकि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध, हलाल मांस, लाउडस्पीकर पर अजान जैसे मुद्दों ने मुस्लिम समुदाय को प्रभावित किया, जबकि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में उल्लिखित समान नागरिक संहिता जैसे व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की मांग की और 4 की हड़ताल की। मुसलमानों सेः कोटा, यद्यपि इसने प्रमुख रूप से हिंदू समुदाय से वोट प्राप्त करने का प्रयास किया, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

कांग्रेस के समर्थन में रहने वाले अधिकतर लोग इस आशा में थे कि यदि कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो अन्न भाग्य योजना से उन्हें लाभ होगा, परंत, मौजूदा स्थिति कुछ और है। यदि कांग्रेस लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकती थी तो उसे सुधारों की स्थिति और लोगों पर इसके प्रभाव का भी अनुमान लगाना चाहिए था ।

इसलिए, ये कुछ कारण थे जिनके कारण 2023 में कर्नाटक में दलीय प्रणाली में परिवर्तन आया, तथापी कांग्रेस ने गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं होने के बावजूद बहुमत सीटें प्राप्त कीं, हम उन योजनाओं को लागू करने में कुछ मुद्दों को देख सकते हैं। कोई भी सरकार शासन करे, लोगों को विकास देखना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा।

ऐसे कुछ विकास कार्य हैं जो भाजपा ने 2019 में अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर सड़कों जैसे पूरे किए हैं, अब हम देख सकते हैं कि कैसे बेहतर सड़कों के कारण शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रामीण श्रमिकों के लिए समय की कम खपत होती है, जिससे उनका जीवन बेहतर होता है आर निर्धनता पर अंकुश लगाया जा सकता है।

यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में लोग विशेष रूप से मतदान के लिए पार्टी के स्थान पर उम्मीदवार के आधार पर वोट देते हैं, जो उन्हें लगता है कि सुधार ला सकता है, इसलिए कर्नाटक में दलीय प्रणाली में परिवर्तन लाने वाले कारकों में से मतदाताओं के लक्ष्य व आशाओं में परिवर्तन

के कारण कांग्रेस को अधिकांश वोट प्राप्त हुए व सत्ता दल के रूप में काँग्रेस ने कर्नाटक राज्य में अपने को स्थापित कर लिया।

♦♦♦♦♦

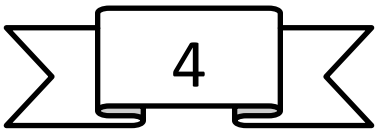

कर्नाटक की चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार का परिवर्तनीय परिदृश्य

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में परस्पर चुनावी प्रक्रिया का होना अति–आवश्यक है, चुनाव लोकतंत्र का वह अभिन्न भाग है जो लोकतंत्र को जीवंत रखता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वैधता (Legitimacy) को बनाये रखने के लिए चुनाव एक तरह से मुख्य उपकरण के रूप में माना गया है। मतदताओं की इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए चुनावों द्वारा वैधता लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक तरह से लोगों के लिए सच्ची अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते है। इस अनुरूप वैधता के पैटर्न को समझने के लिए मतदाताओं के परिवर्तनीय मतदान व्यवहार को भी समझना महत्वपूर्ण है। चुनावी त्योहार के दौरान मतदान व्यवहार का अध्ययन इसलिए अधिक आवश्यक हो जाता है, की लोग किसे वोट देंगे एवं उनकी प्राथमिकताएं क्या है। विचारों की बहुलता चुनावी प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक कर देती है, मतदातओं का उत्साह, राजनेताओं के वादे एवं राजनीतिक दलों की आपस में प्रतियोगिता और टकराव चुनावी परिदृष्य को और नजदीक से देखने को मजबूर करता है। इसलिए यह लेख 2023 के कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों पर आधारित है जिसमें की कैसे कर्नाटक के लोगों का मतदान व्यवहार भिन्न–भिन्न कारकों, निर्धारकों, परिस्थितियों एवं नये परिवर्तनों से राज्य की चुनावी राजनीति का परिदृश्य कैसे परिवर्तित हुआ है, उसका एक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

भौगोलिक स्थिति से अगर कर्नाटक को देखा जाए तो वह चार भिन्न–भिन्न भागों में वर्गीकृत है, जिसमें कलबुर्गी, बेलगावी, मैसूर और बेंगलुरू सम्मिलित है। कर्नाटक के ये चार क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से भिन्न–भिन्न एवं नये और नवीन परिवर्तनों को दर्शाते है। चुनावी समीकरण एव द्रष्टिकोण से देखा जाये तो कर्नाटक की राजनीति में तीन मुख्य दलों को देखा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर), तीनों दलों ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अपनी राजनीतिक पारी को मतदाताओं के मध्य अधिक सुदृढ़ और परिपक्व करने का प्रयास किया।

इसी अनुरूप यह देखा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनावों की राजनीतिक पारी में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और मतदताओं के मध्य अधिक मजबूती के साथ पायी गयी। कांग्रेस ने 224 में से 135 विधानसभा सीटों पर अपनी चुनावी जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 66 सीटों पर एवं जनता दल (सेक्युलर) ने 19 पर, और 3 सीटों पर अन्य व निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे अधिक 42.9 प्रतिशत मिला, भारतीय जनता पार्टी को 36 प्रतिशत, एवं जनता दल (सेक्युलर) को 13.3 प्रतिशत, और 7. 8 प्रतिशत मत अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ।

इन चुनावी आकड़ो से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मतदाताओं के मध्य अपनी नीतियों एवं चुनावी वायदों द्वारा एक मजबूत पकड़ बनाने का काम किया जो कि वास्तविक परिणामों में भी परिवर्तित हुआ जिससे कर्नाटक की चुनावी राजनीति में एक नया परिदृ श्य देखने को मिला। कांग्रेस के चुनावी वायदे जैसे की, पुरानी पेंशन योजना पर निर्णय लेना एवं विचार करना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा का वायदा करना, युवाओं के लिए युवा निधि योजना, इत्यादि मतदाताओं को ज्यादा आकर्षित करने में सफल रहे। वही दूसरी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदे चाहे वो राशन से संबंधित हो, या शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित हो वह सब मतदताओं पर अधिक प्रभाव नही डाल पाए अतः इसके विपरित कांग्रेस अपने चुनावी वायदों द्वारा लोगों का भारी मत प्राप्त करने में सफल रही। वही अगर जनता दल (सेक्युलर) की बात करे तो वह 2023 के विधानसभा चुनावों की दौड़ में काफी पीछे रही और किंगमेकर की भूमिका में न रहकर वह 19 सेटों तक ही सिमट कर रह गयी, पार्टी को पारंपरिक कुछ विधानसभा सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई, जैसे कि मैसूर की कुछ सीटों पर वह सफल रही, परन्तु बाकी सभी विधानसभा सीटों पर ज्यादातर पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा।

कर्नाटक विधानसभा 2023 के चुनावों के संदर्भ में मतदातओं के मतदान व्यवहार को एक नए परिवर्तन के अनुसार देखा जा सकता है जिसमें की मतदाता का मतदान व्यवहार रैशनल पैटर्न (Rational Pattern) के अनुसार देखा जा सकता है, जहा मतदाता चुनावों के समय अपने फायदे या नुकसान का आकलन करता नजर आता और वह उसे ही अपना मत देता है जिस्से उसका स्वार्थ अधिक पूर्ण हो सके। दूसरा परिवर्तन जो जुड़ा है वह राजनीतिक दलों से है जिसमें यह देखा जा सकता है कि अब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कैसे नियमित सेवाओं की जगह चुनावी वायदों द्वारा फ्री की सेवाओं की घोषणाएं की जाती है जिस्से की मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके और वोट पा सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रकार से अपने आपको पुनः जीवंत करने के लिए संजीवनी बूटी की तरह है, कर्नाटक की विजय यात्रा के पश्चात् अब कांग्रेस का भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनावों में किस प्रकार प्रदर्शन रहता है यह देखना दिलचस्प होगा, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने आपको और सजग एवं परिपक्व रूप से आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस या अन्य के क्षेत्रिय दलों के मुकाबले सुदृढ़ता से रखती है यह भी आने वाले समय में एक नए भारत में परिवर्तित हुए चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार के परिवर्तित एव परिवर्तनीय परिदृश्य को प्रस्तुत करेगा।

♦♦♦♦♦

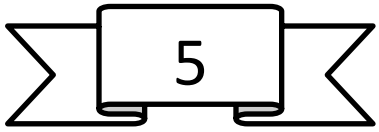

कर्नाटक में युवाओं के मतदान व्यवहार का एक अध्ययन

हदुंगरा नरजरें

विधार्थी, राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय

यह लेख दिल्ली विश्वविद्यालय का वैश्विक अध्ययन केंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए सर्वेक्षण सी जी एस समीक्षा द्वारा भारत के कर्नाटक राज्य में युवाओं के मतदान व्यवहार का परीक्षण करता है। उन कारकों को समझने में महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करता है जो चुनावों में युवाओं की भागीदारी, मतदान प्राथमिकताओं और क्षेत्र में लोकतंत्र पर प्रभाव को प्रभावित करते हैं। सी जी एस समीक्षा की प्रश्नावली कर्नाटक में युवाओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और एन वोटिंग ब्लॉक के रूप में उनके महत्व पर चर्चा से शुरू होती है। यह उन कारकों पर प्रकाश डालता है जो युवा राजनीतिक भागीदारी को आकार देते हैं, जैसे शिक्षा, सोशल–मीडिया, साथियों का प्रभाव और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि। 2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक में 15–29 वर्ष आयु वर्ग के 2.1 करोड़ युवा हैं। यह आलेख कर्नाटक में युवाओं के मतदान व्यवहार पर उपस्थित शोध का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। सरकार चुनने के लिए ज्ञान आवश्यक है, एक लोकतांत्रिक समाज में, स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टिकोण रखने में सक्षम एक सर्वोत्म जनसंख्या युवाओं है। राज्य में चुनाव लोकतंत्र को ओर अधिक सुदृढ़ करते है।

हाल के वर्षों में, भारत में युवाओं के मतदान व्यवहार ने अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिसका मुख्य कारण उनकी बढ़ती चुनावी शक्ति और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है। कर्नाटक एक जीवंत और राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य, इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। इस लेख का उद्देश्य कर्नाटक में युवाओं के मतदान व्यवहार, उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों और हाल के चुनावों में देखे गए उभरते रुझानों की खोज करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक में 15–29 वर्ष आयु वर्ग के 2.1 करोड़ युवा हैं। बेंगलुरु में सबसे अधिक युवा हैं, उसके पश्चात् बेलगावी, बल्लारी, मैसूरु और कलबुर्गी हैं। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के मध्य अत्यधिक अंतर है। बेंगलुरु में 21.73%, बेलगावी में 7%, बेलारी में 4.92%, मैसूरु में 4.77% और कलबुर्गी में 4.22% है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, कोडागु जिले में युवा जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। असमानता को नजरअंदाज करना कठिन है।

कुछ प्रमुख कारकों पर विचार–विमर्श किया गया है।

1. सामाजिक–राजनीतिक जागरूकता और भागीदारीः कर्नाटक में युवाओं के मध्य सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने उनके मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी तक पहुंच के साथ, आज के युवा पहले से कहीं अधिक सक्रिय हैं। वे सक्रिय रूप से विचार–विमर्श और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, अपनी राय बनाते हैं और अपने मतदान निर्णयों को प्रभावित करते हैं (डी. चक्रवर्ती और के. जयश्री, 2018)।

2. पार्टी संबद्धता और वैचारिक संरेखणः पार्टी संबद्धता प्रायः मतदान व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्नाटक में, युवा खुद को उन राजनीतिक दलों के साथ जोड़ते हैं जो उनकी आकांक्षाओं, विश्वासों और विचारधाराओं से मेल खाते हैं। पार्टी घोषणापत्र, करिश्माई नेतृत्व और सोशल मीडिया अभियानों का संयोजन युवाओं को एक विशिष्ट पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है (ए.के. नायक, 2016)।

3. युवा–विशिष्ट नीतियां और अभियानः राजनीतिक दलों ने युवा वोट बैंक को लक्षित करने के महत्व को पहचाना है और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए युवा–विशिष्ट नीतियां और अभियान बनाना शुरू कर दिया है। रोजगार सृजन, कौशल विकास, शिक्षा सुधार और उद्यमिता प्रोत्साहन जैसी पहल कर्नाटक में युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पार्टियाँ युवा समर्थन प्राप्त करने में सफल रही हैं (एस. शिल्पी और आर. सिंह, 2017)।

4. क्षेत्रवाद और अस्मिता की राजनीति का प्रभावः विविध संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान वाले कर्नाटक में सामान्यतरू मतदान व्यवहार पर क्षेत्रवाद और अस्मिता की राजनीति का प्रभाव देखा जाता है। विशिष्ट क्षेत्रों या भाषाई समूहों से संबंधित युवा उन पार्टियों का समर्थन करते हैं जो उनकी संबंधित पहचान की वकालत करते हैं या उनके क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने का वादा करते हैं, यह पहलू कर्नाटक में युवाओं के मतदान व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (एम. एस. वीरेंद्र और के. रंजना, 2018)).

5. सेलिब्रिटी समर्थन और सोशल मीडिया प्रभावकों की भूमिकाः सेलिब्रिटी समर्थन और सोशल मीडिया प्रभावकार युवाओं का ध्यान आकर्षित करने और उनकी मतदान प्राथमिकताओं को प्रभावित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं। किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय आंकड़े युवाओं में महत्वपूर्ण उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उनके मतदान व्यवहार पर असर पड़ता है (पी.जी. पाटिल, और पी.के. हवानागी, 2015)।

6. मतदाता जागरूकता और शिक्षाः कई अध्ययनों ने चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में मतदाता जागरूकता अभियान और नागरिक शिक्षा कार्यक्रमों की भूमिका पर जोर दिया है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को चुनावी प्रक्रिया, उम्मीदवारों और मुद्दों के बारे में सूचित करना और शिक्षित करना है, जिससे उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके (वर्मा, 2017य गोयल, 2019)।

7. प्रौद्योगिकी और सोशल मीडियाः शोध से पता चला है कि कर्नाटक में युवा राजनीतिक जानकारी तक पहुंचने, राजनीतिक चर्चाओं में सम्मिलित होने और अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का तेजी से उपयोग कर रह हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक लामबंदी और युवा मतदाताओं तक पहुंचने के महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं।

8. युवा और क्षेत्रीय राजनीतिः अध्ययनों ने जांच की है कि क्षेत्रीय भावनाएं और पहचान की राजनीति कर्नाटक में युवाओं के मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में युवा उन पार्टियों या उम्मीदवारों के साथ जुड़ सकते हैं जो उनके क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मतदान पैटर्न (श्रीकृष्ण और तेनजिन, 2018) पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

9. जाति और युवा मतदानः कर्नाटक में युवा मतदान व्यवहार को आकार देने में जाति की गतिशीलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई जाति आधारित लामबंदी रणनीतियाँ विशिष्ट जाति समूहों से संबंधित युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं (किशोर और किशोर, 2018, कुलकर्णी, 2019)।

निष्कर्षः

कर्नाटक में युवाओं का मतदान व्यवहार अब केवल जाति या पारिवारिक प्रभाव जैसे पारंपरिक कारकों से प्रेरित नहीं है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रदर्शन, इंटरनेट की पहुंच और बढ़ती जागरूकता के साथ, युवा अपने मतदान निर्णयों में अधिक समझदार और आलोचनात्मक हो गए हैं। सामाजिक–राजनीतिक जागरूकता, पार्टी संबद्धता, युवा–विशिष्ट नीतियां, क्षेत्रवाद और प्रभावशाली लोग कुछ प्रमुख कारक हैं। कर्नाटक में युवा वोट सुरक्षित करने का लक्ष्य रखने वाले राजनीतिक दलों के लिए इन प्रभावों और उभरते रुझानों को समझना आवश्यक है।

संदर्भ–सुची

- Chakraborty, D., & Jayashree, K. (2018). Voting Behaviour among Youth in India: A Comparative Study, 141-148.
- Mudde, Raggi (2016), "Population of Karnataka"
- Nayak, A.K. (2016). Political Participation of youth in Karnataka: A Study with special reference to Electoral Politics. South Asian Journal of social Sciences and Humanities, 157-164
- Shilpi, S., & Singh, R. (2017). Importance of Youth in Politics: A Study on Voting Behaviour of young voters in Karnataka, 7-13.
- Virendra, M.S., & Rajanna, K. (2018). Political Participation of Urban Youth in Karnataka: An Empirical Study, 68-81.
- Patil, P.G., & Havanagi, P.K. (2015). Youth and Electoral Politics: A case Study of Karnataka State Legislative Elections 2013. In Indian Youth and Electoral Politics, 85-96.
- Verma, K. (2017). Impact of voter awareness campaigns on youth engagement in elections. International Journal of Political science, 45-61.
- Geol. P. (2019). Civic education and youth voter participations. A case study of Karnataka. 123-140.
- Shrikishna, K.R., & Tenzin, D. (2018). Technology and political participation of youth in Karnataka. International Journal of Communication and Media Studies, 78-95.

♦♦♦♦♦

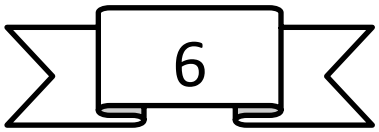

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्वः कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में एक अध्ययन

चंद्रिका आर्य

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जब जब लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों आदि चुनावों के परिणाम घोषित होते हैं, तब तब हम देखते हैं कि इन परिणामों में महिलाओं की संख्या ना के बराबर होती हैं। यद्यपि कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर ही नहीं अपितु कई स्थानों पर तो पुरुषों से भी अधिक है। परंतु इसके बावजूद महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या की तुलना में बहुत कम है। अभी हाल ही में आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो पाएंगे कि यहां पर भी महिलाओं की वही स्थिति है जो भारत के अन्य प्रांतों की विधानसभाओं और संसद के दोनो सदनों में है। प्रश्न है कि क्यों महिला उम्मीदवारों की संख्या चुनावी परिणामों में न्यून के बराबर होती है और क्यों उन्हें प्रतिनिधित्व से अदृश्य कर दिया जाता है?

महिलाओं को चुनावी टिकट न देने का चलन

कर्नाटक राज्य की की विधानसभा सीटों पर ध्यान देते है तो पता चलता है कि 224 विधानसभा सीटों में 112 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। अर्थात 50 फीसदी सीटों पर महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में अधिक शक्ति है । परंतु इस सबके बावजूद जीतने वाले उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण यह रहा है कि महिलाओं को चुनाव ही नही लड़ने दिया जाता, जैसे हम देखें तो पाएंगे कि इस बार कर्नाटक चुनाव में कुल 2613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे परंतु इनमें से महिलाओं की संख्या केवल 185 थी जो कि कुल संख्या का केवल 7.07 फीसदी ही बनता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने से कतराते हैं जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने अपने कुल 224 उम्मीदवारों में से केवल 12 महिलाओं को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने 223 में से केवल 11 वहीं जनता दल सेकुलर ने 207 में से 13 महिलाओं को टिकट देकर चुनाव लडने का मौका दिया, जिनमें से

बीजेपी और कांग्रेस की क्रमशरू पांच व चार महिला उम्मीदवार वहीं जेडीएस की एक महिला और एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने मं कामयाब रही। यहां साफ है कि यदि ज्यादा महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता तो निश्चित रूप से ज्यादा महिलाएं विधानसभा में प्रवेश करती और महिलाओं के हित के लिए नीतियों के निर्माण में योगदान दे पाती।

उच्च साक्षरता–दर महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़न में रही बेअसर

कर्नाटक राज्य में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर शिक्षा का भी कोई सीधा असर नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि कर्नाटक में साक्षरता दर 75.36 प्रतिशत है पंरतु प्रदेश में अब तक हुए 16 विधानसभा चुनावों में ये केवल चौथी बार हुआ है कि कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं की संख्या ने दहाई का आंकड़ा छुआ है और स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक के सभी चुनावों में कुल 1114 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी हैं जिनमें से 102 ने जीत दर्ज करके विधानसभा में प्रवेश किया है। वहीं दूसरी तरफ इस राज्य में आज तक केवल 13 महिलाएं ही लोकसभा सांसद बन पाई हैं जो कि संख्या की दृष्टि से बहुत कम है।

ये आश्चर्य की बात है कि भारत की संसद में पहली बार 1996 में जब 81वें संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व बिल प्रस्तुत किया गया, तब देश के प्रधानमंत्री आज की जनतादल सेकुलर पार्टी के मुखिया एचडी देवगौड़ा ही थे, वहीं इस महिला प्रतिनिधित्व बिल को दूसरी बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में बीजेपी ने संसद में पेश किया और 2010 में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में इस बिल को न केवल पेश किया अपितु 186 वोटों के साथ इसे संसद की उच्च सदन में पास भी करवाया। पंरतु फिर भी तीनों राजनीतिक दलों ने महिलाओं को चुनावी मैदान से दूर ही रखा।

महिलाएं मतदाता से महिला उम्मीदवार या विधायक क्यों नहीं बन पाई?

यदि हम महिलाओं की राजनीति में भागीदारी मतदाताओं के रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। चाहे बात आम चुनावों की हो या विधानसभा चुनावों की भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं अपने मताधिकार का महत्व जानकर बड़े स्तर पर मतदान के लिए बाहर आ रही हैं। इस संदर्भ में वर्ष 2019 के आम चुनाव में भारतीय महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पछाड़कर इसे एक ऐतिहासिक चुनाव के रूप में याद करने योग्य बनाया है। ये भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना है कि 1961 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 16.73 प्रतिशत कम था जो कि बीते चुनाव में पुरुषों को पर कर गया है। भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की ओर इसे एक बड़ा कदम

मानते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा इस घटना को आत्म सशक्तिकरण की मौन क्रांति का नाम दिया गया है। 1990 के दशक से बढ़ रही महिला मतदाताओं को संख्या के पीछे राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अनेकों कारण दिए जाते हैं जैसे कि महिलाओं में बढ़ती साक्षरता दर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वृद्धि, डिजिटल क्रांति, महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कुछ विशेष कदम तथा पंचायतों व नगर निगम में महिलाओं के लिए आरक्षण।

यहां पर सोचनीय विषय यह है कि महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या महिला उम्मीदवारों व महिला विधायकों की बढ़ती संख्या में परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रही है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का मतदान पुरुषों के मुकाबल केवल 0.98 प्रतिशत कम है परंतु चुनाव जीतने के मामले में ये महिलाएं केवल 5.3 प्रतिशत सीटें ही जीत पाई है। महिलाएं मतदान के लिए तो बाहर निकली हैं परंतु नेता के रूप में या विधायिकाओं में इनकी संख्या नही बढ़ पा रही। राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के पीछे आज भी वही पुराने घिसे पीटे संस्थागत व संरचनात्मक कारक विद्यमान है जो महिलाओं को नेतृत्व के पदों तक जाने से रोकते हैं।

संस्थागत बाधाएं

चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की संख्या कम होने का एक बड़ा कारण यह भी है की महिलाओं को राजनीतिक दलां द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है। उनके साथ यह धारणा जुड़ी हुई है कि महिला उम्मीदवार पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखती है। महिला उम्मीदवारों के साथ चुनाव जीतने की अयोग्यता जुड़ने के कारण राजनीतिक दल उन्हें पार्टी टिकट देने में संकोच करती है। पुरुष राजनेताओं द्वारा महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को कम आंकना व उन्हें कमजोर समझना महिलाओं के राजनीति में कम प्रतिनिधित्व का मुख्य कारण है। यही कारण है कि महिलाओं कि मतदान में अधिक भागीदारी होने के बाद भी उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया जाता जिसके चलते महिला उम्मीदवार चुनावी परिणामों में अदृश्य मिलती हैं और यदि महिलाएं टिकट पाकर चुनाव जीत भी गई हैं तो उन्हें कोई भी नेतृत्व का पद देने में पार्टी असहज महसूस करती है।

महिला मतदाताओं की अधिक संख्या व उनके कम प्रतिनिधित्व से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि राजनीतिक दल महिला मतदाताओं का प्रयोग केवल वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं। जिसके लिए राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव प्रचार करते हैं साथ ही महिला मतदाताओं के लिए चुनाव के समय बहुत बड़े–बड़े वायदे करते हैं जैसे कि मुफ्त गैस सिलेंडर देना, मुफ्त परिवहन सेवा देना, महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देना आदि। राजनीतिक दल महिलाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं चाहे वह महिला मतदाता के रूप में हो या पार्टी वर्कर

के रूप में हो क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि महिला मतदाताओं के साथ–साथ महिलाओं की भूमिका पार्टी वर्कर के रूप में भी बढ़ी है। बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं जैसे कि चुनावी रैलियों में भाग लेना, घर घर जाकर चुनाव प्रचार करना, चुनावी पंपलेट का वितरण करना आदि। इसका अर्थ है राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए महिलाओं का बखूबी प्रयोग करते हैं चाहे वह मतदाता के रूप में हो या पार्टी वर्कर के रूप में परंतु जब बात महिला सशक्तिकरण की आती है तो राजनीतिक दल एक संकुचित रुख अपनाते हैं। अपने मताधिकार के लिए जागरूक तथा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद राजनीतिक संस्थाओं से महिलाओं को दूर रखना हमारी राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों की रूढ़िवादी सोच को इंगित करता है।

संरचनात्मक बाधाएं

इसके अतिरिक्त कुछ चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक स्थितियां भी महिलाओं को राजनीति तक जाने से रोकती हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि राजनीति केवल पुरुषों का ही कार्य है और महिलाएं इसके लिए उचित उम्मीदवार नहीं है। समाज में श्आंतरिक पितृसत्ताश होने के कारण महिलाओं की भूमिका केवल घर के कामकाज व बच्चों की देखरेख तक ही सीमित कर दी जाती है जिसके चलते वह राजनीति के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाती हैं। यह समझा जाता है की महिलाओं के पारिवारिक दायित्व के लिए प्रतिबद्धता अधिक है इसलिए वह राजनीति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करने के पश्चात भी भारत में पब्लिक–प्राइवेट के बीच एक सख्त दीवार है जिसके तहत घर के कामकाज को महिलाओं का कार्यक्षेत्र माना जाता है। तथापि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ी है। बहुत सारे अपारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को न केवल प्रवेश मिला है अपितु उन्होंने बहुत से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परंतु इसके साथ उन्हें घर के कामकाज से मुक्ति नहीं मिल पाई है जिसका कारण है की घर संभालने के दायित्व को महिलाओं की प्राथमिकता मानकर उन्हें राजनीति के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं समझा जाता है।

भ्रष्ट चुनावी व्यवस्था

भारतीय चुनाव व्यवस्था की दो बड़ी कमियां है Money power और Muscle power जिसका चुनाव के दौरान जमकर प्रयोग होता है। चुनाव में पैसे का अंधाधुंध प्रयोग होने के कारण भारत में राजनीति में कैरियर बनाना एक महंगा विकल्प है जिसके चलते महिलाएं राजनीति में कैरियर बनाने से वंचित रह जाती है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव अगर किसी उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंदी का मजबूती से मुकाबला करना है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए

अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में वित्तीय व्यवस्था करना महिला उम्मीदवारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जो राजनीति में उनके प्रवेश को बाधित करता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अधिकांश वही महिलाएं अपनी पहचान बना पाई हैं जो बड़े घरानों से संबंध रखती हैं या जिनके राजनीति में पारिवारिक संबंध है।

निष्कर्ष

इसके लिए न केवल महिलाओं को आगे आकर अपना अधिकार मांगना होगा, अपितु पुरुषों को भी महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि ये साफ है कि जिन राज्यों या देशों का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में हैं उन राज्यों या देशां ने आपातकाल या किसी महामारी के समय अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के रूप में जब कोरोना ने विश्व में तबाही मचाई तब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री एक महिला थी और उन्होंने अपने देश में अत्यधिक उत्कृष्ट माध्यम से कोरोना का सामना किया और अत्यधिक उत्कृष्ट माध्यम से अपने देश को इस वैश्विक महामारी से बाहर निकालने में सफल रही। इसके साथ ही वही समाज या देश विकास के शिखर को छू पाते हैं जहां पर अर्ध–जनसंख्या को भी पूर्ण भागीदारी मिलती है। इस दिशा में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र तथा महिला आरक्षण बिल की सुदृढ़ इच्छाशक्ति कुछ आवश्यक कदम सिद्ध हो सकते है।

♦♦♦♦♦

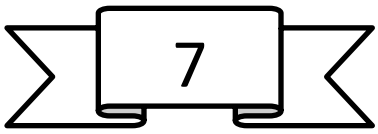

कर्नाटक की चुनावी राजनीति में परिवर्तित प्राथमिकताओं के मध्य जनता दल (सेक्युलर) की परिस्थिति

डॉ काजल

राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों में, किंगमेकर से लेकर एक छोटे राजनीतिक खिलाड़ी तक, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) की राजनीतिक गति धीमी हो गई है। अपने गठन के पश्चात से ही, जेडी (एस) ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ सरकारें बनाई है। कर्नाटक में दल औसतन 30 से 40 सिटें जीतता था। 2004 से 2018 के मध्य किंगमेकर की भूमिका निभाते हुए तीन बार कर्नाटक विधान सभा चुनाव में त्रिशंकु परिणाम रहे। किंतु 2023 में, 2018 के विधान सभा चुनावों से विजयी सिटें 37 से घटकर 20 रह गई हैं, जिसका अंतर मत प्रतिशत में 5 प्रतिशत के अंतर से दिखता है, जो 2018 में 18.3 प्रतिशत था किंतु अब 13.3 प्रतिशत रह गया है। जो 2004 के चुनाव के बाद से अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। 2023 के कर्नाटक चुनाव में जेडी(एस) ने स्पष्ट रूप से किंगमेकर होने व एचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया था। वास्तव में बहुत–से ओपिनियन पोल के माध्यम से भी त्रिशंकु सरकार के बनने और जेडी (एस) की अहम भूमिका निभाने का दावा किया गया। किंतु चुनाव परिणामों में विपरीत स्थिति रही। बहुत–से चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, जेडी (एस) के वोक्कालिगा सहित अधिकतम मतदाताओं ने कांग्रेस को प्राथमिकता दी। इस लेख का उद्देश्य 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तथा भाजपा की तुलना में जेडी (एस) की चुनावी स्थिति का मूल्यांकन करना व उनकी चुनावी विफलता का विश्लेषण करना है।

दक्षिण कर्नाटक की चुनावी प्रतिस्पर्धा

प्रधानमंत्रो नरेंद्र मोदी के कर्नाटक में प्रचार अभियान के साथ, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका वाड्रा के व्यापक दौरे के साथ, दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपनी चुनावी गति बढ़ा दी थी। जिसके कारण कर्नाटक के कुछ क्षेत्र भाजपा बनाम कांग्रेस रहे किंतु दक्षिण कर्नाटक में यह जेडी (एस) बनाम कांग्रेस के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और भाजपा

दोनों के लिए ही, विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए सम्भावनाएं दक्षिण कर्नाटक पर टिकी हुई थी, जो मुख्यतः जेडी (एस) का प्रबल क्षेत्र माना जाता रहा है।

2006 के विधानसभा चुनावों में इसी क्षेत्र से क्षेत्रीय दलों ने 58 सीटें प्राप्त की थी और भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी, जो सत्ता से पहला कार्यकाल था। कहीं न कहीं भाजपा को प्रारंभ से ही यह आशा रही कि दक्षिण में जेडी (एस) की जीत से उनको लाभ हो सकता है। कर्नाटक के दो बड़े समुदाय, वोक्कालिगा और लिंगायत के मतों को लेकर भाजपा, कांग्रेस और जेडी (एस) के मध्य प्रतिस्पर्धा थी और दोनों ही समुदाय दक्षिण कर्नाटक में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। दक्षिण कर्नाटक में अपना स्थान बनाने के लिए भाजपा ने प्रचार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चयन किया, जो मुख्यतः वोक्कालिगा समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मठ 'आदिचुनचुनागिरी मठ' के अध्यक्ष थे। यह संपूर्ण प्रचार भाजपा के लिए 60 सीटों का आधार था, जो चामराजनगर से बेंगलुरु ग्रामीण तक विस्तारित है। वहीं मठ से अतिरिक्त मतों की संख्या जेडी (एस) को अपने समर्थन में आती दिखाई दे रही थी।

वरुणा क्षेत्र में, कांग्रेस चुनाव प्रचार में सक्रिय रही जो सिद्धरमैया का चुनावी क्षेत्र है। जहां से विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर बोम्मई सरकार द्वारा आरक्षण नीति की घोषणा चुनाव यात्रा की गई। किंतु यह सिट कांग्रेस द्वारा ही जीती गई।

कुल मिलाकर कित्तूर, कल्याण, मध्य, तटीय, दक्षिण कर्नाटक और बेंगलुरु में कांग्रेस को अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कांग्रेस ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। किंतु दक्षिण कर्नाटक के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से भाजपा के प्रबल क्षेत्र थे, उनमें भाजपा ने अपना वोट शेयर खो दिया। बढ़त के रूप में भाजपा को दक्षिण कर्नाटक में सफलता मिली किंतु वह सफलता किसी नई सिट में परिवर्तित नहीं हो पाई। वहीं जेडी(एस) ने अपने मुख्य समर्थन आधार को खो दिया।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडी (एस) की प्रक्षेपवक्र

कांग्रेस की पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की सफलता जेडी (एस) के लिए चिंता का विषय अवश्य है। एक ओर कांग्रेस ने प्रस्तावित सीटों से 60 सिट अधिक प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर जेडी (एस) केवल 19 सिट जीत सकी, जो 2018 के चुनें की तुलना में आधी सिट हैं। इसी के साथ, 2004 की तुलना में जेडी (एस) का वोट शेयर 20.8 प्रतिशत से घटकर 13.3 प्रतिशत हो गया और उसी अवधि के दौरान उसकी जीती गई सीटों का प्रतिशत 25.9 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हो गया है।

वर्तमान समय में जेडी (एस) को अपने अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसने पुराने मैसूर (अपने प्रबल क्षेत्र) में कांग्रेस और भाजपा को स्थान दे दिया है। जेडी (एस) ने वोक्कालिगा के अपने मुख्य वोटिंग क्षेत्र में अनुमानतः आठ प्रतिशत समर्थन खो दिया है। जिस कारण वह पुराने मैसूर में कांग्रेस से पीछे हो गई है। पुराने मैसूर में जेडी (एस) की संख्या 2018 की स्थिति से आधी हो गई है, जिससे 2023 के विधानसभा चुनावों में इसकी कुल सीटों की संख्या कम हो गई है।

सारणीः 1 पुराने मैसूर में दलों का प्रदर्शनः सीट शेयर

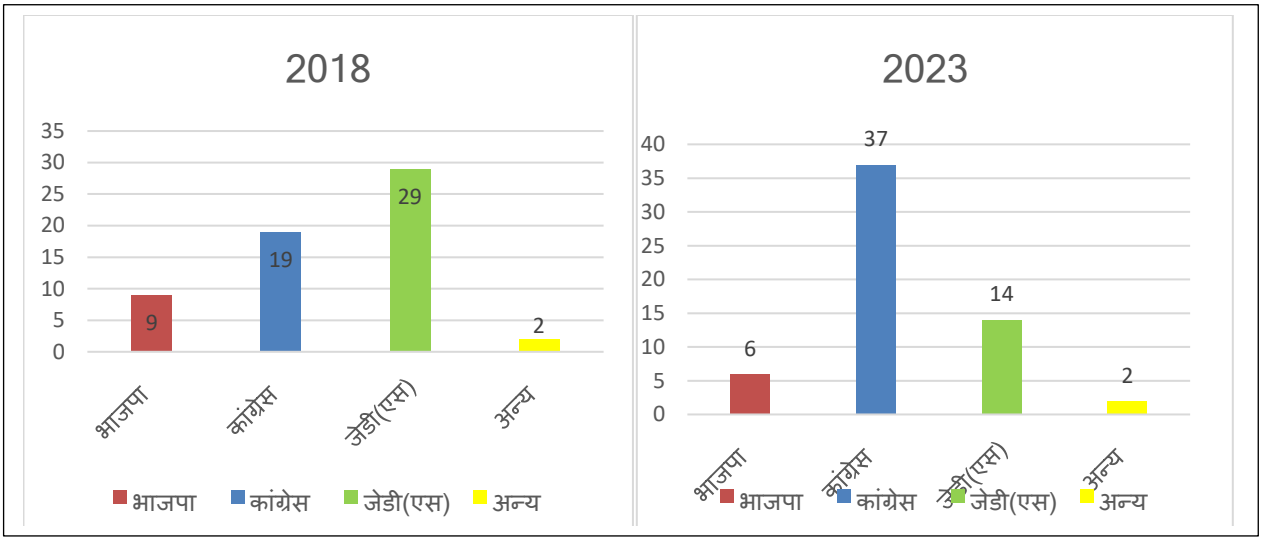

स्रोतः भारतीय चुनाव आयोग, 2023 कर्नाटक चुनाव

जेडी(एस) की विफलता के कारण

- वोक्कालिगा समुदाय के मत और पुराने मैसूर पर जेडी (एस) की अत्यधिक निर्भरता ने इसे राज्य–वार उपस्थिति प्राप्त करने से रोक लिया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जेडी(एस) के प्रत्येक 10 मतदाताओं में चार वोक्कालिगा हैं।
- जेडी (एस) पर कांग्रेस की "बी टीम" होने का आरोप मतदाताओं ने बहुत–ही गंभीरता से ले लिया। जेडी (एस) द्वारा अस्थिरता उत्पन्न करने वाली बात ने भी उसके विरुद्ध काम किया।
- यद्यपि, जेडी (एस) के लिए सबसे बड़ा झटका कर्नाटक चुनावों का शीघ्रता से द्विध्रुवीय हो जाना था। जिसके चलते आवश्यक रूप से बहुमत तक पहुँच पाना जेडी (एस) के लिए कठिन था।

- अल्पसंख्यकों, दलितों और अगड़ी जातियों का एक वर्ग जेडी (एस) से दूर कांग्रेस के समर्थन में चला गया है। यहाँ तक कि वोक्कालिगा का एक वर्ग (लगभग आठ प्रतिशत) भी कांग्रेस में स्थानांतरित हो गया क्योंकि उन्हें डीके शिवकुमार में एक मुख्यमंत्री पद की उम्मीद दिखी।
- मांड्या शहर क्षेत्र में, दल के भीतर मतभेद और उपस्थित विधायक पूर्व सांसद शंकर गौड़ा के पोते विजयानंद (जिन्होंने विद्रोही क रूप में चुनाव लड़ा) का दल के विरुद्ध जाना जेडी (एस) के लिए बड़ी क्षति थी। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का इस बात से रुष्ट होना कि एच डी कुमारस्वामी यह सोचकर इस क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने में विफल रहे कि यह एक सुरक्षित सिट है।
- हसन क्षेत्र में भी स्थिति कुछ समान ही थी जहां जेडी (एस) को 2023 विधान सभा चुनावों में तीन और सीटें हारनी पड़ी। 2018 में, छः में से पाँच सोट जेडी (एस) ने जीती थी। किंतु 2023 में जेडी (एस) बेलूर और सकलेशपुर भाजपा से हार गई जहां वह निरंतर जीत प्राप्त करती आ रही थी।

कुल मिलाकर 2023 कर्नाटक विधान सभा चुनाव ने दलों के प्रबल वोट बैंक को केवल खंडित ही नहीं किया अपितु विभिन्न समुदायों की मतदान प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन को प्रदर्शित किया है।

♦♦♦♦♦

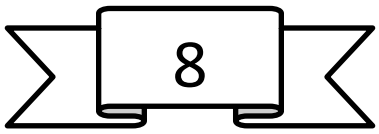

कर्नाटक विधानसभा चुनावः 2018 व 2023 का एक तुलनात्मक अध्ययन

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधालय

कर्नाटक विधानसभा के सभी 224 सदस्यों को चुनने के लिए 10 मई 2023 को कर्नाटक में विधान सभा चुनाव हुए। जिसका परिणाम 13 मई 2023 को चुनाव में काँग्रेस ने प्रभावशाली विजय से आया । इस चुनाव में 73.19 मतदान हुआ, जो कर्नाटक के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान था।

2018 में हुए कर्नाटक विधासभा चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किन्तु कर्नाटक 2023 में भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव जीतने में असफल रही।

2018 में चुनाव जोतने के निम्न कारण देखे जा सकते हैः–

मोदी मैजिकः– कर्नाटक में भाजपा के जीतने का सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में किसी प्रमुख दक्षिणी राज्य में उसकी पहली बड़ी जीत थी। 2016 में हुए तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार नहीं कर सकी। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से हटने के साथ, भाजपा ने दक्षिण में एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो दिया है। हिंदी को थोपने, पंद्रहवें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों आदि मुद्दों पर असहमति इन राज्यों में भाजपा के लिए कठिनाईयां उत्पन्न कर रही है। सिद्धारमैया ने भी अपने स्वयं के कन्नड़–राष्ट्रवाद के माध्यम से भाजपा के हिंदुत्व के प्रयास का मुकाबला करने का प्रयास किया है। भाजपा की जीत यह संकेत दिया कि वह इन सभी चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है और एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है।

इसके साथ ही, 2018 के कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के सॉफ्ट हिन्दुत्व के विचार कॉग्रेस के काम नहीं आया। कॉग्रेस नेता अधिकतर मठों व मंदिरों में गए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचारों को अभिव्यक्त करने व जनता को प्रभावित करने कोई विकल्प नहीं था। राहुल गांधी बिना पेपर को पढे बिना 15 मिनट तक भी नहीं बोल सकते थे। इसी प्रकार के अन्य कारण भी थे जो काँग्रेस की पराजय व भाजपा के विजय का कारण बने।

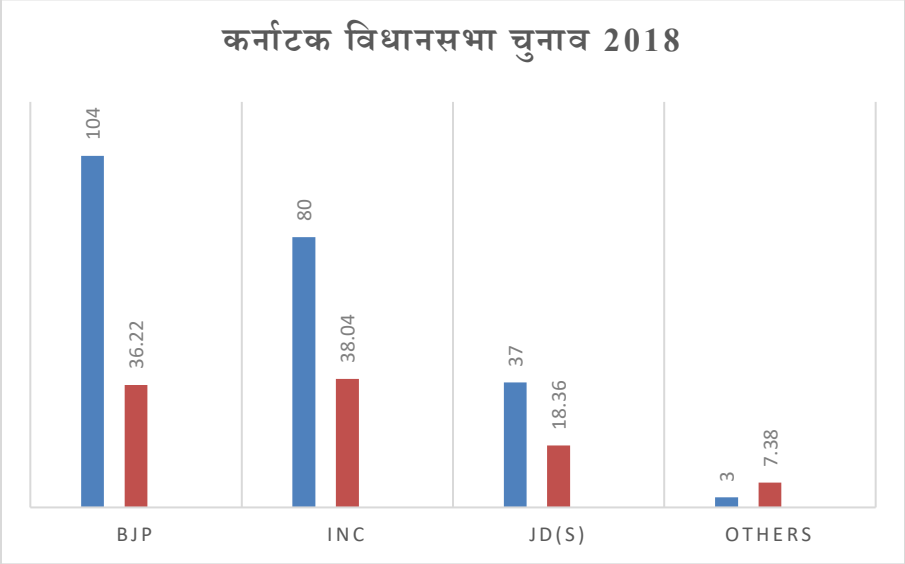

स्रोतः भारतीय चुनाव आयोग, 2018 कर्नाटक चुनाव

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा ने 104 सीटों पर विजय प्राप्त की। वहीं कॉंग्रेस के पास मात्र 80 सीट ही आ पाई। इसके साथ ही, जेडीएस मात्र 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं अन्य के पास 3 सीट आई।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023

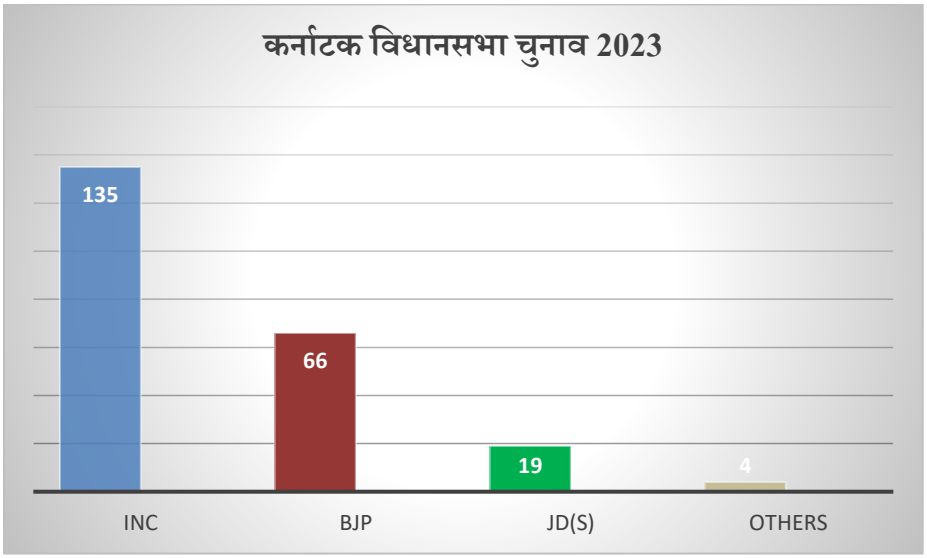

स्रोतः भारतीय चुनाव आयोग, 2023 कर्नाटक चुनाव

जबकि 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा मात्र 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। और विजेता के रूप में कॉंग्रेस दल ने 135 सीटें जीतकर कर्नाटक मे अपनी सरकार बनाने में

सफल रही। जेडीएस के भाग में मात्र 18 सीट ही आ पाई और अन्य दलां के पास 4 सीट ही आ पाई।

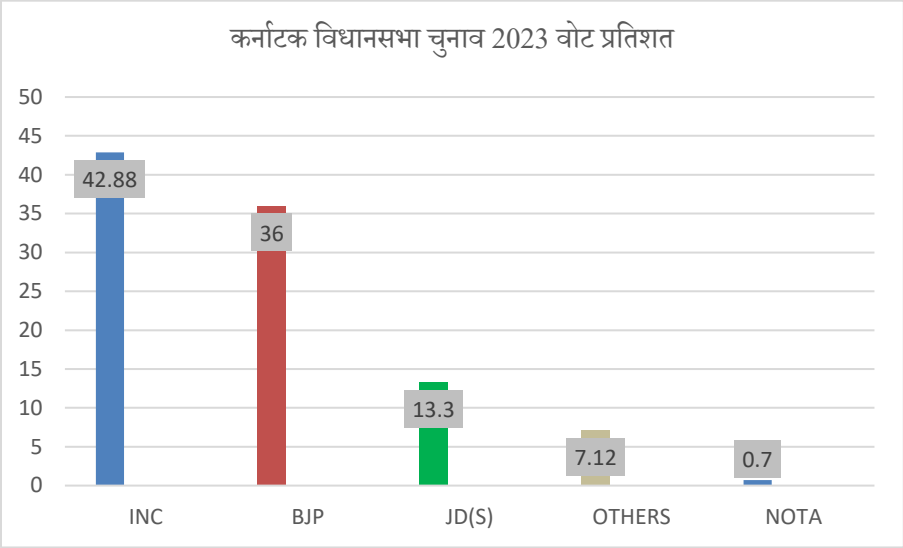

स्रोतः भारतीय चुनाव आयोग, 2023 कर्नाटक चुनाव

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में काँग्रेस का मत प्रतिशत 42.88 था। जबकि भाजपा का मत प्रतिशत 36 ही था। जेडीएस का मत प्रतिशत 13.3 था और वहीं अन्य दलों का मत प्रतिशत 7.12 था। जबकि 0.7 प्रतिशत ऐसे मतदाता थे जिन्होंने किसी भी दल को अपना मत नहीं दिया, नोटा का प्रयोग किया।

भाजपा की पराजय व काँग्रेस के विजयी होने के निम्न कारण देखे जा सकते है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान

पार्टी नेताओं के अनुसार, 40 प्रतिशत कमीशन सरकार जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ–साथ अदानी मुद्दे के साथ भाजपा सरकार पर पार्टी के चौतरफा हमले ने लोगों को प्रभावित किया। भ्रष्टाचार का यह मुद्दा कर्नाटक में कॉग्रेस के विजेयी होने अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा।

खैरात की प्रत्याभूति

चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्याभूति देने का वादा किया था। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन गारंटियों को मुफ्त की संस्कृति की श्रेवड़ीश संस्कृति के रूप में स्थापित किया था, ऐसा लगता है कि यही प्रत्याभूतियाँ कांग्रेस के इंजन को अत्यधिक बढ़ावा दे रही हैं। जिसमें मुख्यतरू 200 यूनिट सभी घर में मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी। तथा अन्न भाग्य योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त प्रदान किया

जाएगा। इसके अतिरिक्त, गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये की प्रत्येक माह सुविधा प्रदान की जाएगी। तथा इसके साथ ही, 2 वर्ष के लिए प्रत्येक डिप्लोमा कोर्स करने वाले विधार्थी को जिसकी आयु 18 से 25 वर्ष की होगी, 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे और प्रत्येक स्नातक युवा को 3000 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे।

मुस्लिम वोटों का एकीकरणः– कांग्रेस नेताओं के अनुसार, एक अन्य प्रमुख कारक मुस्लिम वोटों का एकीकरण था, जो मतदाताओं का लगभग 13 प्रतिशत था और सामान्य रूप से, कांग्रेस और जेडी(एस) के मध्य इसके पक्ष में विभाजित होता था। और यही कारण भाजपा मुफ्त दक्षिण भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा ह।

भाजपा की पराजय का प्रभाव आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री का मोदी मैजिक अब अधिकतर राज्यों में काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि भाजपा के पास स्थानीय नेताओं की कमी है। मोदी मैजिक के दम पर भाजपा अधिक समय तक चुनाव नहीं जीत पाएगी। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अरविन्द केजरीवाल और ममता बैनर्जी का कोई विकल्प भाजपा के पास है नहीं, जिससे भाजपा राज्यों मे चुनाव जीतने में सफल हो पाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक मुख्य भाजपा की ओर से स्थानीय नेता है।

विकास व अभिशासनः– कर्नाटक की जनता ने यह प्रदर्शित किया है कि अब राज्यों के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी व हिन्दुत्व जैसे विषयों से काम नहीं चलेगा, दलों को चाहे वो भाजपा हो या काँग्रेस या कोई अन्य दल सभी को राज्य में काम करना पड़ेगा। जनता विकास व अभिशासन चाहती है। बेरोजगारी, महगाई का विषय, मूलभूत सुविधाओं की कमी जिसके अंतर्गत गैस सिलेंडर, राशन सुविधा, पानी की समस्या, विद्यालय व महाविद्यालय व शिक्षा की गुणवत्ता पर भाजपा को कार्य करना होगा।

वर्तमान में राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में काँग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में मात्र भाजपा की सरकार है। वहीं विपक्षी दलों को यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार, ममता बैनर्जी, अखिलेश यादव व शरद पवार जैसे नेता आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधनीय सरकार के रूप में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते है। अतः आने वाला लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए भी और अन्य दलों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।

मुख्यतः इस आलेख में देखा जा सकता है कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के मतदाताओं को प्रभावित करने वाले थे उन मुद्दों ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रतिकूल कार्य किया। वहीं काँग्रेस ने जिन मुद्दों के बल पर 2018 के चुनाव में सरकार बनानी

चाही, वहाँ कॉंग्रेस विफल रही। 2018 से 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस ने अपने मुद्दों में परिवर्तन किया। जिससे कॉंग्रेस 2023 में कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। लोकतंत्र में यहीं महत्वपूर्ण है, जनता प्रत्येक पाँच वर्ष में किस दल को अपनी वरीयता दे, यही लोकतंत्र की विशेषता है।

♦♦♦♦♦

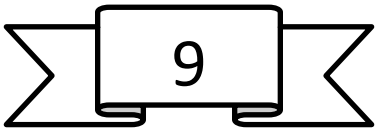

कर्नाटक विधानसभा चुनावः एक विश्लेषण

सुमेर राम

विद्यार्थी, हिन्दू कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधालय

दक्षिणी भारत की राजनीति में कर्नाटक राज्य में 16वीं विधानसभा के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। कर्नाटक चुनाव के राजनीतिक अर्थ में न केवल दक्षिणी भारत की राजनीति तक सीमित है अपितु इनको उत्तरी भारतीय राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। चूंकि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव छः माह पश्चात् दिसंबर में ही प्रस्तावित है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव भी ठीक एक वर्ष पश्चात् ही होने है ऐसे में कर्नाटक चुनाव विभिन्न अर्थों में अधिक निर्णायक प्रतीत होते है। हिमाचल प्रदेश के पश्चात् निरंतर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक 135 सीटों (कुल 224 में से) पर विजय प्राप्त करना, अपनी खोई सत्ता पाने के लिए संघर्षरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए औषधि सा है। निःसंदेह रूप से आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए यह जीत प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगी तथा कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा का भी संचार करेगी। वही सतारूढ़ विजयी रथ पर आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक राज्य में 66 सीटों पर सिमट जाना और हिमाचल प्रदेश के पश्चात् कर्नाटक राज्य में भी सत्ता से बेदखल हो जाना, उसके विजयी रथ के लिए समस्या उत्पन्न करता है। इसे बीजेपी को राजनीतिक सीख के रूप लेना चाहिए। निसंदेह कर्नाटक के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अस्वीकृत कर दिया हो किन्तु बीजेपी यदि इस चुनाव से सीखे सबक को मध्य नजर रखकर आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में उतरे तो निश्चय ही बेहतर स्थिति में होगी। इस लेख में कर्नाटक चुनाव से बीजेपी को मिलने वाली सीख एवं चुनाव में प्रभावी मुद्दों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया जो कि निम्न प्रकार है–

चुनाव में प्रभावी प्रमुख मुद्देः

वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित 'सीजीएस समीक्षा 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव सर्वेक्षण' के अन्तर्गत आधारिक स्तर पर आम मतदाताओं से रूबरू होते समय

निम्न चुनावी मुद्दे सामने आए जो कि चुनाव में निर्णायक सिद्ध हुए। जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है।

- भ्रष्टाचार कांग्रेस ने भाजपा की बोम्मई सरकार के विभिन्न "कथित घोटालों" और ठेकेदारों के निकाय द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन शुल्क पर विशेष बल देते हुए बोम्मई सरकार को '40% कमीशन सरकार' सरकार के रूप में प्रस्तुत कर भ्रष्टाचार को अपने चुनाव अभियान का एक केंद्रीय विषय बनाया। इसके साथ स्थानीय स्तर पर जनता में भी इसे लेकर भारी आक्रोश नजर आया। वही बीजेपी ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पिछले कांग्रेस शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार, विशेष रूप से सिद्धारमैया सरकार द्वारा कथित नोटबंदी घोटाले को मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया।
- महंगाई एवम् बेरोजगारी दृ कांग्रेस एवम् जेडीएस ने मूल्य वृद्धि को एक प्रमुख मुद्दा बनाया विशेष रूप से "उच्च" रसोई गैस और ईंधन की कीमतें के मुद्दे को बनाया तथा कांग्रेस ने महंगाई को नियंत्रित करने के वादे किए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों एवम् छोटे शहरों में बेरोजगारी भी एक प्रमुख मुद्दा था। अधिकांश युवा अपने स्थाई रोजगार को लेकर चिंतित नजर आए।
- विकास एवम् कल्याणकारी योजनाएंः भाजपा ने मतदाताओं का मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण की पहलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया तो वही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनकल्याण हेतु 5 वादे किए जिनको लेकर मतदाताओं में अत्यंत उत्साह था। और यह अत्यधिक निर्णायक भी सिद्ध हुए जैसे– गृहलक्ष्मी– घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा, गृह ज्योति– राज्य के बीपीएल अर्थात निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना, अन्न भाग्य– बीपीएल परिवार अर्थात निर्धनता रेखा के नीचे आने वाले परिवार को 10 किलोग्राम चावल देना, शक्ति– राज्य की हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा एवम् युवा निधि– बेरोजगार ग्रेजुएट को दो साल तक 3000 रुपये प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति महीना देने का वादा इत्यादि।
- साम्प्रदायिकता और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीतिः कांग्रेस ने भाजपा पर हिजाब, हलाल, अजान और टीपू सुलतान जैसे विभाजनकारी मुद्दों को चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाने के आरोप लगाए जबकि भाजपा ने कांग्रेस को बजरंग दल के बैन को लेकर

कठघरे में खड़ा किया। तथा इसे प्रत्येक चुनावी सभा में कांग्रेस को जमकर घेरा तथा कांग्रेस को हिंदू विरोधी दल के रूप में चित्रित करने का प्रयास। किन्तु बीजेपी का यह माध्यम अधिक सफल सिद्ध नही हो पाया।

बीजेपी के लिए सीख

सतारूढ़ एवं लम्बे समय से विजय रथ पर आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक चुनाव में पराजय एक सीख के समान है। बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव दिसंबर 2023 में प्रस्तावित 5 राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवम् मिजोरम के चुनाव मई, 2024 में प्रस्तावित आम चुनाव 'महा मुकाबले' से पूर्व सेमीफाइनल के लिए भी एक चेतावनी के रूप में है। कर्नाटक चुनाव से बीजेपी को कइ निम्न सबक सीखने होंगे जिससे कि आगामी चुनावों की राह सुगम हो सके–

- स्थानीय राजनीतिक चेहरे का अभाव समाप्त करनाः निसंदेह राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पास मोदी व शाह जैसे चेहरे है जिनके दम पर चुनाव जीते जा सकते है, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है कि इन्हीं के दम पर विधानसभाओं के चुनाव जीते जाए चूंकि विधानसभा चुनाव एवं आम चुनावों के मुद्दों व कार्ययोजनों में गहन अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि बीजेपी को मोदी शाह पर अति निर्भरता को कम कर स्थानीय स्तर के नेता तैयार करने होंगे। असम, उत्तरप्रदेश एवम् गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी के स्थानीय नेताओं का प्रभावशाली होना लाभदायक सिद्ध हुआ। वही पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवम् कर्नाटक में इनकी कमी खलती रही है।
- आयातित नेताओं के स्थान पर पार्टी के निष्ठावान नेताओं पर विश्वासः भाजपा को हानि पहुंचाने में दूसरे दलों से आयातित करके लाए गए नेताओं की भी भूमिका रही। उन पर अतिविश्वास एवम् पार्टी के पुराने कार्यकर्ता एवम् नेताओं के स्थान पर उनको टिकट वितरण करना अत्यधिक अनुपयोगी सिद्ध हुआ। निसंदेह सरकार बनाने के लिए उन्हें साथ लिया गया हो, परंतु जब विरोधी माहौल बनना शुरू हुआ तो उन्होंने पुराने दलों में लौटने में देर नहीं लगाई। और कुछ आयातित नेता जो चुनाव में भले ही बीजेपी के साथ रहे हो, परंतु वो कुछ विशेष काम नहीं कर सके। तथा जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं का भिन्न रूख अपनाना भी भाजपा के विरोध में गया।

वही कांग्रेस द्वारा चुनाव से अधिक पहले टिकट वितरण व टिकट वितरण में वर्षों से आधारिक स्तर पर काम करने वालों कार्यकर्ताओं को वरीयता देते हुए उचित टिकट प्रबंधन अत्यधिक निर्णायक सिद्ध हुआ।

- कमजोर, अक्षम एवम् निष्क्रिय स्थानीय नेतृत्वः भाजपा ने चुनावों से लगभग 2 वर्ष पूर्व बीएस येदियुरप्पा के स्थान पर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी का यह निर्णय अधिक सफल सिद्ध नहीं हुआ। बोम्मई की सरकार को भ्रष्टाचार के कारण 40 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार के रूप में जाना गया दृ जिसका मुखिया अक्षम, विभाजित और एक कमजोर नेतृत्व के रूप में था। भारत की ज्ञान राजधानी कहे जानी वाले बेंगलुरु का बुनियादी ढांचा चरमरा गया था, सड़कों पर गड्ढों, बार–बार बाढ़ आने, प्रदूषित झीलों और ट्रैफिक जाम के कारण होने वाली मौतों की संख्या चिंताजनक थी। कृषक वर्ग परेशान थे और बेरोजगारी भी एक प्रमुख समस्या थी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जनकल्याण को वरीयताः इसके अतिरिक्त जनकल्याण को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर वरीयता देनी चाहिए, बेशक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दूरगामी परिणाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक आवश्यक है, किन्तु यह दृश्यमान विकास है इसकी निर्माण अवधि लंबी है। जैसा कि 2004 के इंडिया शाइनिंग अभियान के साथ हुआ था, निर्धनों को लगता है कि उन्हें आमतौर पर इन परियोजनाओं से लाभ नहीं होता है और वे वास्तव में उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली नौकरियों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मेगा परियोजनाएं वोट–कैचर नहीं हैं। इसको भी बीजेपी को मध्य नजर रखना होगा। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र आज भी कोविड के प्रभाव से उभर रहे हैं, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से आज भी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है बीजेपी को इन 'योजनाओं को रेवड़ी या मुफ्तखोरी' की योजना नाम देने के स्थान पर इस पर विचार करना चाहिए।
- तटस्थ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास हिंदुत्व एकमात्र बीजेपी को सभी राज्यों के चुनाव में विजयी नही दिला सकता। ऐसे में बीजेपी को तटस्थ और स्विंग मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनको प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि तटस्थ एवम् स्विंग मतदाता किंगमेकर की भूमिका में होते है। इसलिए बीजेपी को अपने विकास एजेंडे, व्यापार और निवेश अनुकूल नीतियों, राष्ट्रवाद और पीएम मोदी के सुदृढ़ नेतृत्व से इस वर्ग को अपने ओर आकर्षित करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए।

निष्कर्षः

कर्नाटक चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए महामुकाबले (आम चुनाव 2024) से पूर्व एक चेतावनी के रूप में है, तथापि विधानसभा चुनावों एवम् आम चुनाव के मुद्दे एवम् प्रकृति में अत्यधिक अंतर होता है। चूंकि 2018 में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवम् राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी किन्तु मात्र छ माह पश्चात हुए आम चुनाव में बीजेपी ने इन राज्यों में भारी बढ़त प्राप्त की थी। किन्तु फिर भी बीजेपी को भले ही आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से ही सही कर्नाटक चुनाव परिणाम से सबक सीखने होंगे। वही कांग्रेस के लिए भी बहुत सी सीख है। जिस पर उन्हें ध्यान देना होगा जैसे कि कर्नाटक में विजय मात्र उनके संगठनात्मक सुदृढ़ता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता व एक सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी दल के रूप वापसी की वजह से ही नही अपितु बीजेपी की कमजोर व अक्षम स्थानीय नेतृत्व, कार्ययोजना की कमी एवम् संगठनात्मक ढांचे में तोड़ मरोड़ की वजह से भी सुनिश्चित हो पाई है। इस प्रकार कर्नाटक चुनाव के परिणाम दोनों ही दलों के लिए विभिन्न सीख के रूप है, जो कि कर्नाटक के साथ– साथ सम्पूर्ण भारत के भी लोकतंत्र के संवर्धन में उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक चुनाव में मतदान व्यवहार पर दृष्टि डाले तो यहां परिवर्तनीय लोकतांत्रिक परिदृश्य नजर आता है। क्योंकि कर्नाटक का मतदाता अधिक जागरूक प्रतीत हो रहा है। अब वो अत्यधिक नाप तोल कर अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए मतदान कर रहा है। राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता एवम् विचारधारा जैसे अप्रत्यक्ष मुद्दों के स्थान पर रोजगार, स्वास्थ्य जैसे प्रत्यक्ष सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहा है। वही राष्ट्रीय मुद्दों के साथ–साथ स्थानीय मुद्दों को भी समान रूप से महत्व दे रहा है।

♦♦♦♦♦

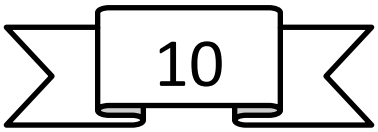

उत्तरी कर्नाटक में मतदान व्यवहार की परिवर्तित प्रकृतिः बेलगावी क्षेत्र का एक अध्ययन

दृष्टि साह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्षों से चुनावी राजनीति भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को महत्वपूर्ण रूप से पकड़ने में सक्षम रही है। मतदाताओं के मतदान व्यवहार के लेंस के माध्यम से यह अध्ययन कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के अनुसार मतदाता की चुनावी प्राथमिकताओं के अनुभवजन्य अनुसंधान को लाने का प्रयास करेगा। यह पेपर चुनावी राजनीति में एक नागरिक – संस्था केंद्रित के आसपास विकसित मतदान व्यवहार के मौलिक विरोधाभास को बताता है। इसे देखते हुए, यह अध्ययन बेलगावी मतदाता के मतदान व्यवहार के साथ समझा जा सकता है जो चुनावों की परस्पर संबंधित भूमिकाओं को दर्शाता है। राजनीतिक परिदृश्य में चुनावी भागीदारी, प्राथमिकताएं और मतदान प्रतिशत महत्वपूर्ण होते है, इनसे एक मतदाता की पसंद एवं उसके मूल्यांकन को समझने में सहायता रहती है जो एक लोकतांत्रिक राजनीति के अभिविन्यास को दर्शाता है। नतीजतन, चुनावी राजनीति के सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक आधार पर मतदाता के व्यवहार को अध्ययन किया जा सकता है। एक मतदाता के जीवन में मतदान के क्षण की जांच करना महत्वपूर्ण हो जाती है जो गोपनीयता की वर्जना के साथ एक ढाल है। इसलिए यह लेख इस अनुरूप कर्नाटक विधानसभा चुनावों की पहेली में मतदान व्यवहार की बदलती प्रवर्ति एव प्रकृति का एक अध्ययन है।

लोगों, स्थानों और विवरणों का चिह्नित करते हुए कर्नाटक के जनसांख्यिकीय मानचित्र को चार अलग–अलग डिवीजनों में रेखांकित किया गया है, जैसे कि कलबुर्गी डिवीजन हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्रों को कवर करता है, बेलगावी या बेलगाम डिवीजन मुंबई कर्नाटक को वर्गीकृत करता है, मैसूर डिवीजन तटीय कर्नाटक को प्रदर्शित करता है और बेंगलुरु डिवीजन मध्य कर्नाटक को कवर करता है। प्रत्येक राजनीतिक विभाजन ने कर्नाटक शहर के राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त भूमिका निभाई है। इसी अनुरूप इस लेख द्वारा कर्नाटक के बेलगावी क्षेत्र के मतदाताओं के मतदान व्यवहार की प्रकृति को डिकोड करने पर अधिक बल दिया गया है। बेलगावी क्षेत्र का चुनावी माहौल दो प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक मजबूत मुकाबला देखा

गया, जिन्होंने चुनावों के वैकल्पिक वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है। यहां, 2023 के विधान सभा चुनावों में देखे गए मतदाताओं की वरीयताओं और मतदान प्रतिशत का गहन विश्लेषण प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

पेपर का मुख्य उद्देश्य हाल के वर्षों में मतदाताओं के मतदान व्यवहार की प्रकृति में दर्शाए गए बदलते परिदृश्य पर बारीकी से अध्ययन करना है। इसमें, मतदान के पैटर्न को विभिन्न चरणों में विभिन्न दलों के लिए चुने गए व्यक्तिगत उम्मीदवारों के रूप में नामित तीन प्रचलित मापदंडों के माध्यम से बदलती चुनावी राजनीति का अध्ययन किया गया है। पहला, व्यक्तिगत उम्मीदवारी को मुख्य रूप में रखकर व्यक्तित्व के लक्षणों के माध्यम से करिश्माई नेतृत्व ने मतदाताओं के दिमाग को अलग–अलग तरीकों से कैसे लुभाया है। दूसरा दल की पहचान, इस मापदंड का तात्पर्य राजनीतिक दल की पहचान और उसकी मूल विचारधारा की परीक्षा से है जो मतदाता के मतदान व्यवहार को संचालित करता है। तीसरा मापदंड, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा घोषित नीतियों और कार्यक्रमों से है , जिसको की मतदाताओं के लिए बनाई गई नीतियों के आधार पर पार्टी के प्रदर्शन का गहन आत्मनिरीक्षणता के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। विभिन्न चुनावी कार्यकालों के दौरान मतदाता पिछले कार्यकालों के साथ पार्टी के शासन तंत्र की तुलना करके किस प्रकार अपने मतदान व्यवहार को परिवर्तित करता है यह नतीजतन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मतदान व्यवहार से समझा जा सकता है। नई विचारधाराओं एवं नीतियों के माध्यम से मतदाताओं में पहले विधानसभा चुनाव से वर्तमान तक भिन्न –भिन्न परिवतन देखे जा सकते है।

दिलचस्प बात यह है कि शहर के मतदाताओं ने राजनीतिक परिदृश्य को इस तरह से बदल दिया है कि इससे राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक एक वैकल्पिक राजनीति का उदय हुआ है। यहां, कोई भी शासन की प्रेरक शक्तियों को भी समझ सकता है जो फिर से उम्मीदवारी के नेतृत्व वाली राजनीति से एक नए परिदृश्य की ओर अग्रसर हो गयी है जिसमे मुद्दों के नेतृत्व वाली राजनीति अब अधिक प्राथमिक एवं प्रबल हो गई है। 2023 में हुए कर्नाटक के वर्तमान विधान सभा चुनावों को देखते हुए, कोई भी यह देख सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में जीती गई सीटों के तुलना में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 224 में से 135 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। वोट शेयर के मामले में, पार्टी 42.9ः हासिल करने में सक्षम रही है जो कर्नाटक के वर्ष 2008 के विधानसभा चुनावों से प्राप्त सबसे अधिक वोट शेयर है। विशेष रूप से, चुनावी वर्ष 2023 में बेलगावी डिवीजन के लिए मतदाताओं की वोट वरीयताओं के स्थानिक विश्लेषण को भारत के चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए सांख्यिकीय आंकड़ों से समझा जा सकता है।

ग्राफ– 1, कर्नाटक के 2023 विधानसभा चुनाव में बेलगावी डिवीजन की वोट प्राथमिकताएं

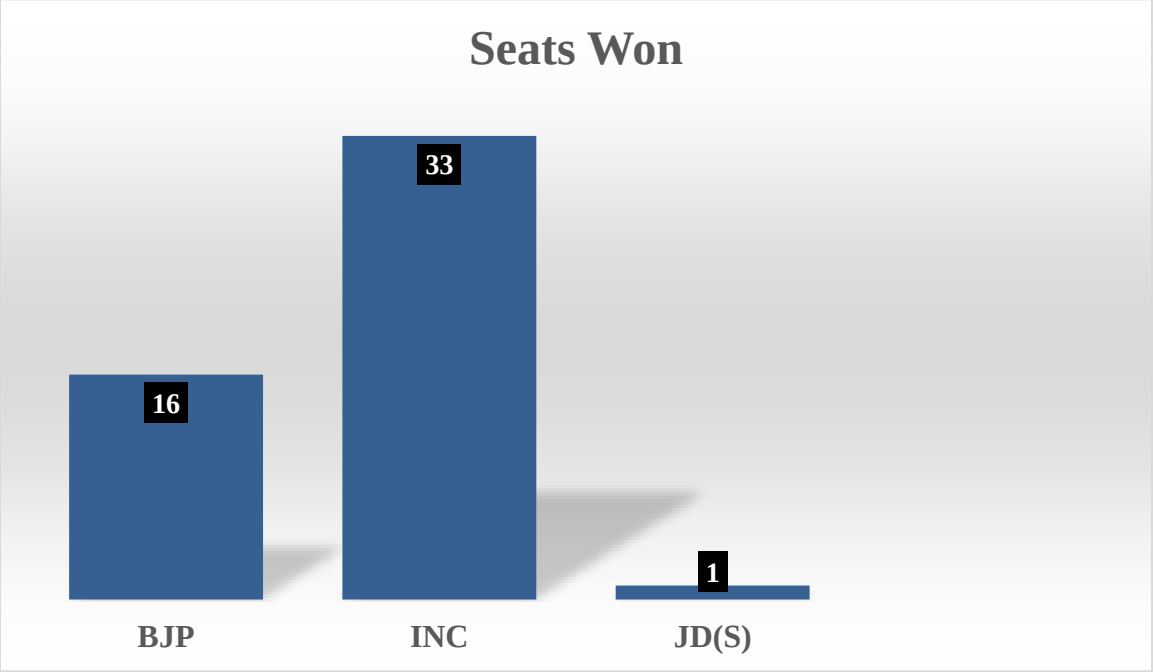

स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग, कर्नाटक के विधान सभा चुनाव 2023।

सीटों के बंटवारे को देखें तो कर्नाटक की 50 विधानसभा सीटों पर बेलगावी क्षेत्र का कब्जा है. जैसा कि ग्राफ 1 में दिखाया गया है, कोई भी देख सकता ह कि 2023 के विधानसभा चुनाव में, बेलगावी क्षेत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा जीता गया है, जिसने 16 सीटों के साथ भाजपा को पीछे छोड़ते हुए 50 में से 33 सीटें हासिल की हैं। इस सफल पारी के पीछे स्थानीय मुकाबला और जमीनी स्तर पर पार्टी का मजबूत नेतृत्व रहा है। पार्टी को व्यक्तिगत उम्मीदवारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मूल निवासियों के साथ स्थानीय रूप से जुड़ने में सक्षम थी। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान ने मतदाताओं के दिमाग को बड़े पैमाने पर ढाला था। लिंगायत और मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों के समुदायों के बीच सोशल इंजीनियरिंग के इर्द–गिर्द प्रचार अभियान विकसित हुआ था। कुल मिलाकर, इसने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के बेलगावी क्षेत्र से 42.6ः वोट शेयर के लिए प्रेरित किया। यह डेटा मुख्य रूप से बेलगावी के ग्रामीण उप क्षेत्रों से लिया गया है, जिन्होंने विभाजन की चुनावी राजनीति की प्रकृति को बदल दिया था।

इसलिए, भारतीय चुनावों को पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों के रूप में देखा जाता है। मतदाता राजनीतिक अभियानों के दिन से सरकार की घोषणा के दिन तक चुनाव की प्रक्रिया को गले लगाता है। इसलिए, राज्य स्तर के चुनावों के मामले में राज्य के निर्वाचकों की राय में अंतर

देखा जा सकता है जब तक कि वे एक राजनीतिक दल के मतदाता नहीं बन जाते। बेलगावी की चुनावी राजनीति को देखते हुए हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि, शहर के दो जनसांख्यिकीय क्षेत्र जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं, जनसांख्यिकीय और लोकतांत्रिक प्रोफाइल को बदलने में मूल पूरक बने हुए हैं। विधानसभा चुनावों की चुनावी राजनीति के प्रक्षेपपथ ने मतदान व्यवहार में बदलाव के साथ राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित किया है। संक्षेप में, बेलगावी क्षेत्र में मतदान व्यवहार की परिवर्तनकारी प्रकृति को इसके मतदान पैटर्न के संदर्भ में समझा जा सकता है जो विचारधारा आधारित मतदान से से मुद्दे आधारित मतदान में परिवर्तित नजर आई है जिसमें मतदाता मतदान करते समय अपने स्वार्थ को देखते हैं। यहां के मतदाताओं ने अपने राजनीतिक अभिविन्यास को संज्ञानात्मक से मूल्यांकनता्मक बनाना शुरू कर दिया है, जहां वे एक राजनीतिक दल की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं एवं चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार में एक नई अवधारणा को प्रदर्शित करते है।

♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281